लोक-सभा वाद-विवाद

tliJ

तिक्षिप्त अनदित ijffiण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

'!ffi"lt' '11{1f

Third Series

खण्ड २५, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXV, 1964/1885 (Saka)

[१० से २१ फरवरी, १९६४/२१ माघ से २ फाल्गुन, १८८५ (शक)]

[February 10 to 21, 1964/Magha 21 to Phalguna 2, 1885 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On 27-5-92
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

(Vol. XXV contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English /Hindi]

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड २५—सातवां सत्र, १९६४]

अंक ६—सोमवार, १७ फरवरी, १९६४/२८ माघ, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२१	जम्मू तथा काश्मीर सीमा (कांगड़ी गांव) पर पाकिस्तानियों द्वारा छापा	३८९—९३
१२२	कपड़ा उद्योग के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड . .	३९३—९४
१२३	फिजो का नागालैंड में प्रवेश . . .	३९४—९९
१२४	आकाशवाणी के लिये नया ट्रांसमिटर . . .	३९९—४०२
१२५	टस्कर परियोजना	४०२—०४
१२६	"सुपरसोनिक" विमानों का निर्माण .	४०४—०६
१२७	हिन्द महासागर में सातवां अमरीकी समुद्री बेड़ा .	४०६—४१०
१२८	तटस्थ देशों का सम्मेलन	४१०—१२
१२९	नेफा में राजनैतिक सुधार	४१२—१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . ४१४—५३

तारांकित प्रश्न संख्या		
१३०	कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना . .	४१४
१३१	छात्रों के लिये सैनिक शिक्षा	४१४—१५
१३२	जम्मू तथा काश्मीर सीमा (कोटमेरा गांव) पर पाकिस्तानियों द्वारा छापा . . .	४१५
१३३	भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां .	४१६
१३४	विदेशों से हथियार	४१६
१३५	सीमा विवादों का निबटारा	४१६—१७
१३६	जंजीबार के भारतीय	४१७—१८
१३७	चिनाकुरी कोयला खान . . .	४१८

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXV—Seventh Session, 1964]

No. 6—Monday, February 17, 1964/Magha 28, 1885 (Saka)

PAGES

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS . . 389—413

*Starred Questions Nos.	Subject	
121.	Raid by Pakistanis on J. &. K. Border . . .	389—93
122.	Second Wage Board for Textile Industry . .	393—94
123.	Phizo's visit to Nagaland	394—99
124.	New Transmitter for A.I.R.	399—402
125.	Tusker Project	402—04
126.	Manufacture of Supersonic Aircraft . . .	404—06
127.	U.S. Seventh Naval Fleet in Indian Ocean . .	406—10
128.	Conference of Non-Alligned Countries . . .	410—12
129.	Political Reforms in NEFA	412—13

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS . . . . 414—53

Starred Questions Nos.		
130.	Family Pension Scheme for Workers . . .	414
131.	Military Training for Students	414—15
132.	Raid by Pakistanis on J. &. K. Border . . .	415
133.	Submarines for Indian Navy	416
134.	Armaments from Abroad	416
135.	Settlement of Border Disputes	416—17
136.	Indians in Zanzibar	417—18
137.	Chinakuri Colliery	418

The Sign † marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर : जारी

तारांकित प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१३८	थुम्बा से राकेट छोड़ना . . .	४१८–१९
१३९	भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण . .	४१९–२०
१४०	जनरल टेलर की यात्रा .	४२०–२१
१४१	चीन द्वारा अतिक्रमण .	४२१
१४२	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का विस्तार	४२१–२२
१४३	पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश	४२२
१४४	लंका में भारतीय उद्भव के राज्यविहीन व्यक्ति .	४२२–२३
१४५	"मिग" विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना .	४२३–२४
१४६	गाजियाबाद के किसान	४२४
१४७	पूर्वी पाकिस्तान में दंगे .	४२४—२६
१४८	वायस ऑफ अमरीका ट्रांसमीटर करार .	४२६–२७
१४९	पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी प्रचार	४२७

अतारांकित प्रश्न संख्या

२३५	आन्ध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार	४२७–२८
२३६	पलना कोयला क्षेत्र, राजस्थान .	४२८
२३७	पंजाब में तकनीकी व्यक्तियों की नियक्ति	४२८
२३८	शिक्षित बेरोजगार .	४२८–२९
२३९	काठमांडू में गांधी स्कूल	४२९
२४०	मैसूर में तकनीकी व्यक्ति . .	४३०
२४१	संयुक्त राष्ट्र महासभा को भारतीय प्रतिनिधि मण्डल .	४३०
२४२	कारखानों में सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था	४३०
२४३	तिरुचिरापल्ली में शस्त्रों का कारखाना .	४३१
२४४	हिन्द महासागर में ब्रिटेन की नौसेना टुकड़ी	४३१–३२
२४५	नाइजेरिया के लिये भारतीय विशेषज्ञ .	४३२
२४६	आकाशवाणी द्वारा संसद् की कार्यवाही सम्बन्धी प्रसारण	४३२–३३
२४७	हथियार बनाने के कारखाने	४३३
२४८	मध्यवर्गीय लोग .	४३४
२४९	अमरीका से हथियार	४३४
२५०	आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकार	४३४–३५
२५१	आसाम के साथ नेफा का एकीकरण	३३५
२५२	वृद्ध और अपंग व्यक्तियों को सहायता	४३५—३६

Subject	PAGE

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

138. Rocket Launching at Thumba . . . . . 418—19
139. Indian Air Space Violations . . . . . 419—20
140. General Taylor's Visit . . . . . . 420—21
141. Chinese Intrusions 421
142. Expansion of U.N. Security Council . . . . 421—22
143. Pak. Infiltration 422
144. Stateless Persons of Indian Origin in Ceylon . . 422—23
145. MIG Aircraft Crash . . . . . . 423—24
146. Ghaziabad Villagers 424
147. Riots in East Pakistan . . . . . . 424—26
148. VOA Transmitter Agreement . . . . . 426—27
149. Anti-Indian propaganda by Pakistan 427

Unstarred Questions Nos.

235. Educated Unemployed in Andhra Pradesh . . . 427—28
236. Palana Coalfield Rajasthan 428
237. Employment of Technical Persons in Punjab . . . 428
238. Educated Unemployed . . . . . . 428—29
239. Gandhi School at Kathmandu 429
240. Technical Persons in Mysore 430
241. Indian Delegation to U.N. General Assembly . . . 430
242. Safety and Sanitary Conditions in Factories . . . 431
243. Arms Factory at Tiruchirapalli 431
244. U.K. Naval Units in Indian Ocean . . . . . 431—32
245. Indian Experts for Nigeria 432
246. Parliamentary Proceedings on A.I.R. . . . . 432—33
247. Ordnance Factories 433
248. Middle Class 434
249. Arms from U.S.A. 434
250. Staff Artists of A.I.R. . . . . . . 434—35
251. Integration of NEFA with Assam 435
252. Assistance to Old and Handicapped Persons . . . 435—36

प्रश्नों के लिखित उत्तर : जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२५३	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	४३६
२५४	दक्षिण भारत में आण्विक विद्युत् केन्द्र	४३६
२५५	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि और महंगाई भत्ता	४३६–३७
२५६	केन्द्रीय सूचना सेवा	४३७–३८
२५७	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग	४३८
२५८	उद्योग में संयक्त प्रबन्ध परिषदें	४३८–३९
२५९	सैनिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण	४३९
२६०	सरकारी कर्मचारियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण	४३९–४०
२६१	ब्रिटेन के जहाज की भारत यात्रा	४४०
२६२	सैनिक स्कूल	४४०–४१
२६३	आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना	४४१
२६४	भारतीय नौसेना के लिये युद्धपोत	४४२
२६५	सामूहिक संचार	४४२
२६६	एशियाई प्रसारक सम्मेलन	४४२
२६७	यात्रा करने वाले सैनिकों के लिये सुविधायें	४४३
२६८	चण्डीगढ़ में क्षेत्र प्रचार अधिकारियों का शिविर	४४३
२६९	"पवित्र बाल" के खोने के सम्बन्ध में आकाशवाणी के प्रसारण	४४३–४४
२७०	घायल सिपाही	४४४
२७१	अणुविक् विज्ञान	४४४–४५
२७२	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये विशेष अधिकारी	४४५
२७३	मनाली-उपशी सड़क	४४५
२७४	महाराष्ट्र में आयुध कारखाना	४४६
२७५	सीमा सड़क संगठन के अधिकारी की मृत्यु	४४६–४७
२७६	नागालैंड में नागा विद्रोहियों की कार्यवाही	४४७
२७७	आर्मी केडेट कालिज, नौगांव	४४७–४८
२७८	इंजीनियरिंग स्नातकों में बेरोजगारी	४४८
२७९	युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि	४४८
२८०	सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड	४४८–४९
२८१	मद्रास का "इण्डियन एक्सप्रेस"	४४९
२८२	सागर जिले में सैनिक क्षेत्र	४४९–५०
२८३	कोचीन के निकट विमान दुर्घटना	४५०

Subject	PAGE
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*	
253. International Film Festival	436
254. Atomic Power Station in South India	436
255. P.F. and D.A. for Industrial Workers	436—37
256. Central Information Service	437—38
257. Publications Division of the I. & B Ministry	438
258. Joint Management Councils in Industry	438—39
259. Training of Army Personnel	439
260. Military Training for Govt. Servants	439—40
261. British Ship's Visit	440
262. Sainik Schools	440—41
263. E.S.I. Schme in Andhra Pradesh	441
264. Frigates for Indian Navy	442
265. Mass Communication	442
266. Asian Broadcasters' Conference	442
267. Amenities for Travelling Troops	443
268. Field Publicity Officers Camp at Chandigarh	443
269. A.I.R. Broadcasts regarding loss of 'Holy Hair'	443—44
270. Wounded Soliders	444
271. Atomic Science	444—45
272. Special Officer for Public Sector Projects	445
273. Manali Upshi Road	445
274. Ordnance Factory in Maharashtra	446
275. Death of Border Roads Organisation Official	446—47
276. Hostile Activities in Nagaland	447
277. Army Cadet College, Nowgong	447—48
278. Unemployment among Engineering Graduates	448
279. Post War Reconstruction Fund	448
280. Soldiers', Sailors' and Airmen's Boards	448—49
281. Indian' Express' of Madras	449
282. Military Area in Saugor District	449—50
283. Flying accident near Cochin	450

प्रश्नों के लिखित उत्तर : जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या — **विषय** — **पृष्ठ**

२८४ आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा ४५०-५१
२८५ कोयला खानों में दुर्घटना ४५१
२८६ परभणी में ट्रांसमिटर ४५१
२८७ केरल के हज यात्री ४५१
२८८ जापान के विमान दल की यात्रा . . . ४५२
२८९ कार्मिक संघों को मान्यता देना ४५२
२९० दक्षिणी, अफ्रीका के साथ व्यापार सम्बन्ध . . ४५३

सदस्य की गिरफ्तारी ४५३

हजरत बल दरगाह से पवित्र बाल की चोरी के बारे में वक्तव्य—

श्री नन्दा ४५३-५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४५४-५५

राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहक उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ४५५—७१

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . . . ४५५—५७
श्री रा० गि० दुबे ४५७-५८
श्री ब्रह्म प्रकाश . . . . ४५८—५९
डा० राम मनोहर लोहिया . . . . ४५९—६१
श्री रिशिंग किशिंग . . . ४६१-६२
श्री टे० सुब्रह्मण्यम ४६२-६३
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी . . . . . ४६३—६४
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा ४६४-६५
श्री मणियंगाडन ४६५
श्री नि० चं० चटर्जी ४६५-६६
श्री समनानी ४६६-६७
श्री पु० र० पटेल ४६७-६८
डा० ब० ना० सिंह ४६९
श्री बदरुद्दुजा ४७०
श्री न० रं० घोष ४७०-७१

मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में शुद्धि ४७२

Subject	PAGE
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*	
284. Assam-East Pakistan Border	450—51
285. Accidents in Coal Mines	451
286. Transmitter at Parabhani	451
287. Haj Pilgrims from Kerala	451
288. Visit of Japanese Aircrfaft Group	452
289. Recognition of Trade Unions	452
290. Trade Relations with South African	453
Arrest of Member	453
Statement *re* : theft of sacred relic from Hazratbal	
Shri Nanda	453—54
Papers laid on the Table	454—55
Motion on Address by the Vice-President discharging the functions of the President.	455—71
Shrimati Renu Chakravartty	455—57
Shri R.G. Dubey	457—58
Shri Brahm Prakash	458—59
Dr. Ram Manohar Lohia	459—61
Shri Rishang Keishing	461—62
Shri T. Subramanyam	462—63
Dr. L. M. Singhvi	463—64
Shrimati Jyotena Chanda	464—65
Shri Maniyangadan	465
Shri N. C. Chatterjee	465—66
Shri Samnani	466—67
Shri P. R. Patel	467—68
Dr. B. N. Singh	469
Shri Badrudduja	470
Shri N. R. Ghosh	570—71
Correction to statement by Minister.	472

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, १७ फरवरी, १९६४/२८ माघ, १८८५ (शक)

Monday, February 17, 1964/*Magha* 28, 1885 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Speaker in the chair)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जम्मू तथा काश्मीर सीमा (कांगड़ी गांव) पर पाकिस्तानियों द्वारा छापा

+

*१२१. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री नाथ पाई
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यवन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा
श्रीमती सावित्री निगम
श्री जेधे :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ दिसम्बर, १९६३ को कुछ पाकिस्तानियों ने जम्मू से ६० मील दूर कांगड़ी गांव पर छापा मारा था ;

(ख) यदि हां, तो लूटी गई सम्पत्ति का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनश सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। ३१ दिसम्बर को पाकिस्तान/पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर के नागरिकों के एक दल ने कांगड़ी गांव की एक कपड़े की दूकान को लूटा था। जब हमारे सीमा प्रहरियों ने रोक-टोक की तो छापामार व्यक्ति, चुराये हुए कपड़े के १३ बंडल फेंक कर, युद्ध-विराम रेखा को पार करके भाग गये।

(ग) सीमा पुलिस के सिपाही ऐसे छापों को रोकने अथवा असफल करने के लिए कड़ी निगरानी रखते हैं ।

Shri Vishram Prasad : I want to know whether our Government has lodged any protest with Pakistan or taken any action in regard to the loot by the Pakistanis ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): युद्ध-विराम रेखा पर ऐसी जो घटनायें होती हैं उनकी सूचना सामान्यतया संयुक्त राष्ट्र कार्यवेक्षकों को दे दी जाती है और इस मामले में यह किया गया है। यह आम प्रक्रिया निर्धारित की हुई है।

Shri Vishram Prasad : I want to know whether any action has been taken or settlement made on such reports or our Government is concerned only with reporting the incidents irrespective of any action being taken or not taken.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जैसाकि मैंने बताया है युद्ध-विराम रेखा के किसी भी प्रकार के अतिलंघन के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। यह मामला संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों को सौंप दिया जाता है और आम तौर पर वे यह कह देते हैं कि इस एक पक्ष का अपराध है अथवा दूसरे पक्ष ने युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन किया है। यही सब कुछ सम्भव है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों द्वारा बाद में उपयोग किये जाने के लिए केवल एक अभिलेख रख लिया जाता है अथवा वे किसी कार्यवाही का प्रस्ताव भी करते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सामान्यतया कोई कार्यवाही नहीं की जाती। वे केवल यह बताते हैं कि क्या युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं अथवा पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है अथवा भारत ने।

श्री नाथ पाई : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान ने उसके विरुद्ध भारत के आरोपित अपकृत्यों का पैशाचिक प्रचार करके अपने लिए सहानुभूति प्राप्त कर ली है क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने अपने देश के विरुद्ध पाकिस्तान के वास्तविक अनधिकृत अपकृत्यों का, जिनमें कि आक्रमण, सीमा का अतिलंघन, छापे आदि सम्मिलित हैं उल्लेख करने वाला एक वार्षिक श्वेत पत्र क्यों नहीं तैयार किया ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन। यह तो कार्यवाही के लिए एक सुझाव है परन्तु इन सब बातों का संसद् में उत्तर दिया जाता है। जब कभी प्रश्न पूछे गये हैं हमने उनके अतिलंघनों आदि का पूर्ण विवरण दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इससे सहमत हूं कि यह एक सुझाव है। परन्तु इस सुझाव पर सरकार ने पहले क्यों नहीं विचार किया ? क्या अब यह करने का उनका विचार है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान के इन आक्रमणों के सम्बन्ध मे हमको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिये और उसे परिचालित करना चाहिये । हम इस पर विचार करेंगे ।

Shri Yashpal Singh : In view of the fact that such incidents are recurring time after time and U.N. Observers have failed to take any action whatsoever, what steps are being taken by our Government in this connection. ?

Mr. Speaker : There is no question of having failed.

The Minister without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri) : The reply to what the hon. Member has asked is clear. The complete positon should be understood. The background in which we are working should be kept in mind. Action cannot be taken there every day. It is an issue between two countries and not something just internal. The action taken by the U. N. observers there is, therefore, quite different. What is more important is that our guards there should always be vigilant and in this case you have seen that they have been vigilant and tried to arrest the raiders and averted the imminent damage. This action is taken from both the sides. Especially, our guards have taken such action.

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know as to how much property has been looted by the Pakistanis and whether any steps have been taken to recover it.

Shri Lal Bahadur Shastri : It is not that they have looted and carried away property worth crores of rupees. They try to break in or loot small shops ; such attempts are resisted and the raiders are caught.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस छापे में छापावर लोग युद्ध-विराम रेखा से तीन मील अन्दर घुस आये थे और क्या पाकिस्तानी सेना उनका साथ दे रही थी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध क्या विरोध-पत्र भेजा गया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जो लोग वहां आये थे वे असैनिक व्यक्ति थे तथा राइफलों और अन्य हथियारों से सज्जित थे और उन्होंने बस लुटमार की थी । यदि माननीय सदस्य इस उत्तर से संतुष्ट हो जायें तो मैं उन्हें यह बता दूं कि ऐसी घटनायें बहुत कम होती हैं । १९६३ के पूरे वर्ष में ऐसी केवल पांच घटनायें हुईं और केवल इतनी वास्तविक क्षति हुई कि ५१ पशु ले जाये गये और एक भारतीय मारा गया तथा तीन घायल हुए ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या वे लोग हमारे राज्य-क्षेत्र में घुस आये थे ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सेना उनकी सहायता नहीं कर रही थी । वे केवल पाकिस्तानी असैनिक व्यक्ति थे तथा राइफलों से सज्जित थे ?

श्री रंगा : जब हम संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों से ये शिकायतें करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है? क्या वे लोग मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन करते हैं और फिर यह मालम करते हैं कि हमारी शिकायत सही है अथवा नहीं और क्या वे संयुक्त राष्ट्र को और हमें भी अपनी रिपोर्ट देते हैं और यदि हां, तो इस घटना के बारे में उनकी क्या रिपोर्ट है अथवा उनका क्या निर्णय है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : आम तौर पर जब कोई घटना घटती है और जब उस घटना की रिपोर्ट की जाती है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक, अथवा वह जो भी कोई हों, मौके पर जाते हैं और वे जांच करते हैं और वे यह बताते हैं कि किसने युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन किया है । इस मामले में सैनिक पर्यवेक्षकों ने अपना निर्णय नहीं दिया है । उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार किसी समय सभा पटल पर .....

अध्यक्ष महोदय : अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है ।

श्री रंगा : उस रिपोर्ट के बारे में कोई पत्र रखेगी जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों ने पाकिस्तान द्वारा पहले किये गये आक्रमणों के सम्बन्ध में दी है ? भूतकाल के सम्बन्ध में हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यदि माननीय सदस्य इन सब युद्ध-विराम उल्लंघनों के सम्बन्ध में एक विवरण चाहते हैं तो हम इसे सभा-पटल पर रखने के सम्बन्ध में विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । श्री हेम बरुआ ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि गत पन्द्रह दिनों के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य की युद्ध-विराम रेखा पर अपनी सेनाओं का जमाव किया है और यदि हां, तो पाकिस्तान के इस जमाव के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : इस घटना में, क्या उन्होंने सैनिक जमाव किया है ?

श्री हेम बरुआ : गत पन्द्रह दिनों में और इसकी सूचना भारत सरकार को दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमारा सम्बन्ध इस विशेष घटना से है ।

श्री हेम बरुआ : यह घटना उससे सम्बन्धित है । उन्हें इससे साहस मिला है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं नहीं समझता कि इस घटना का उसके साथ कोई सम्बन्ध है परन्तु जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उससे यदि उनके मस्तिष्क में किसी और क्षेत्र की बात है .....

श्री हेम बरुआ : जी, नहीं ; मुझे सूचना मिली है कि .....

अध्यक्ष महोदय : : शान्ति, शान्ति ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं । समाचारपत्रों में सभी प्रकार के समाचार छपते हैं परन्तु हमें सतर्क रहना है ; और हमारी सेनायें वहां पर हैं और हम रखवाली करते हैं तथा निगरानी रखते हैं ।

श्री अब्दुल गनी गोनी : ये घटनायें, चाहे वे छोटी हों, अथवा बड़ी हों, पाकिस्तान सरकार द्वारा इस क्षेत्र में, वशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में, गड़बड़ी फैलाने के ध्येय से एक सिलसिले में की जाती रही हैं जिससे कि यह प्रश्न बना ही रहे। इसलिए, क्या मैं जान सकता हूं कि सीमा की सेना और सीमा पुलिस को पुनः बलवान बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं इसका उत्तर दे चुकी हूं । सतर्कता बढ़ा दी गई है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों का जो निर्णय हमारे पक्ष में होता है उससे हमें क्या लाभ होता है क्या हमारे राज्य-क्षेत्र के आतलंघन के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकार भी हमें इससे मिलता है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जहां तक मुझे ज्ञात है वे केवल यह कह देते हैं कि अतिलंघन हुआ है और इससे अधिक कुछ नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक अभिलेख रखा जाता है ।

कपड़ा उद्योग के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड

\+

*१२२. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नाथ पाई :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री उमानाथ :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड में कौन कौन से सदस्य होंगे तथा उसके निर्देश-पद क्या होंगे ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित मजूरी बोर्ड के गठन तथा निर्देश-पदों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh : Could the Government give the names of those mills which refused to implement the recommendations of the First Wage Board and the action taken against them ?

Shri R. K. Malviya : Out of 410 mills, 371 have implemented the recommendations in full ; 27 mills implemented them only in parts and some other mills they are yet to be implemented. 15 mills have not implemented them. The Seshadri Committee is enquiring about those mills and its enquiry is almost complete. The reports of the enquiry so far completed has been sent to the State Governments for implementation. Only one mill in Kerala is left and enquiry regarding that mill also would be concluded in this month.

श्री वारियर : मैं नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : अब भी लगभग १५ मिलों में सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं । एक समिति उनकी जांच कर रही है । उस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Yashpal Singh : What is the extent of representation given to the labour Unions by the newly constituted Labour Wage Board ?

Shri R. K. Malviya : Representation to the labour unions will be given in the usual way. Their list has not so far been finalised.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह दूसरा मजूरी बोर्ड होगा और इसलिये पहले बोर्ड ने जो आंकड़े तथा जानकारी एकत्रित की थी उसमें से बहुत को फिर से एकत्रित करना आवश्यक नहीं होगा, क्या सरकार इस बोर्ड के निर्देश-पदों को बनाने तथा इस बार किसी प्रकार की एक समय-सीमा निश्चित करने की बात पर विचार कर रही है जिससे कि कार्य शीघ्रतापूर्वक किया जा सके ?

श्री र० कि० मालवीय : इस बात का निश्चय तो स्वयं मजूरी बोर्ड ही करेगा । उनको इस में समय लगता है । परन्तु प्रयत्न यह होगा कि सिफारिशें यथा सम्भव शीघ्र मिल जायें ।

श्री वारियर : क्या यह आवश्यक है कि पहले मजूरी बोर्ड ने जो जानकारी एकत्रित की थी वह फिर से एकत्रित की जाये और इस मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के लिये अधिक समय दिया जाये ? यदि नहीं, तो इस मजूरी बोर्ड से यह क्यों नहीं कहा जा सकता कि वे अपनी सिफारिशें उस उपलब्ध जानकारी के आधार पर दें ?

श्री र० कि० मालवीय : सिफारिशें तुरन्त ही नहीं दी जा सकतीं । पिछली सिफारिशें जब दी गई थी उस के पश्चात् उद्योग में विकास कार्य हुए हैं और उन पर अवश्य विचार किया जाना है । इसलिये, इस बात का निश्चय करना मजूरी बोर्ड पर ही छोड़ दिया गया है । सिफारिशों को यथासम्भव शीघ्र प्राप्त करने के लिए निस्संदेह ही प्रयत्न किये जायेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : किस समय तक निर्देश-पदों को अंतिम रूप दे दिया जायेगा और किस समय तक यह मजूरी बोर्ड कार्य करने के लिए स्थापित कर दिया जायेगा ?

श्री र० कि० मालवीय : मालिकों तथा मजदूरों के परामर्श में निर्देश-पदों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । जैसे ही उनकी स्वीकृति आ जायेगी निर्देश-पदों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : जितना समय लगने की सम्भावना है उसका कोई मोटा अनुमान है ?

श्री र० कि० मालवीय : इसमें दो महीनों से अधिक का समय नहीं लगना चाहिये ।

फिजो का नागालैंड में प्रवेश

+
श्री नाथ पाई :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री चवन :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० सामन्त :

*१२३. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मणियंगाडन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हिम्मतसिंहजी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री हेम बरुआ :
श्री कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री हेम राज :
श्री कजरोलकर :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री स्वैल :
श्री केप्पन :
श्री ह० च० सोय :
श्री गुलशन :
श्री राम हरख यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा नेता श्री फिज़ो ने नागालैंड में प्रवेश पाने के लिये सरकार की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी प्रार्थना पर विचार किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) श्री फिज़ो ने भारत सरकार से कोई प्रार्थना नहीं की है परन्तु नागालैंड के मुख्य मंत्री को यह सूचना मिली है कि नागालैंड में पुनः शान्ति स्थापित करने के विषय पर वह उनसे तथा उनके सहयोगियों से बातचीत करने का इच्छुक है। नागालैंड सरकार की प्रार्थना पर, भारत सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि यदि वह मुख्य मंत्री द्वारा निर्धारित की गई शर्त पर नागालैंड सरकार से बातचीत करने के लिये भारत आता है तो उसे सुरक्षादान दिया जायेगा ।

श्री नाथ पाई : यह बताया गया है कि बाद में श्री फिज़ो ने सुरक्षादान के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। क्या हम कारण जान सकते हैं ? क्योंकि भारत सरकार ने अपने प्रस्ताव के द्वारा उसे यह बताया है कि उनकी अपनी राय में नागा समस्या का हल तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि वह उनके साथ समझौता न कर ले, क्या हम जान सकते हैं कि बातचीत कहां पर टूटी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हम यह नहीं जानते कि श्री फिजो ने सुरक्षादान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है अथवा नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है यह प्रार्थना नागालैंड सरकार ने भारत सरकार से की थी। हमने समाचारपत्रों में यह पढ़ा है कि नागालैंड में आने और नागालैंड सरकार से बातचीत करने के अपने मूल प्रस्ताव पर स्थिर रहने से उसने मना कर दिया है। परन्तु जहां तक हमें ज्ञात है ऐसा कोई प्रस्ताव श्री फिज़ो से प्राप्त नहीं हुआ है अथवा उसने इसकी पुष्टि नहीं की है कि उसने नागालैंड आने का अपना विचार त्याग दिया है ।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि बावजूद इस बात के कि हमने नागालैंड में एक लोकप्रिय शासन स्थापित कर दिया है, अब दुनिया और भारत को यह दिखाया जा रहा है कि नागालैंड में किस प्रकार फिज़ो की ही बात चलती है क्योंकि नागालैंड के फिजो के साथियों ने अपनी विद्रोही कार्यवाहियां बढ़ा दी हैं और कुछ समय से हमें इससे बड़ी परेशानी हो रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। नागालैंड सरकार यह महसूस करती है कि यदि उनका फिज़ो के साथ, जो कि सरकार के विरुद्ध विद्रोहियों की सहायता करता रहा है, कोई समझौता हो जाये तो वह अधिक अच्छी तरह से वहां शान्ति और व्यवस्था बनाये रख सकती है। क्योंकि स्वयं फिज़ो ने नागालैंड में आने और शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से नागालैंड सरकार से बातचीत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी अतः नागालैंड प्रशासन इससे सहमत हो गया था। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि फिजो ही नागालैंड का प्रशासन चला रहा है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि फिजो ने यह प्रार्थना उस बातचीत के परिणामस्वरूप की थी जो कि उसने प्रधान मंत्री के एक सभा सचिव के साथ की थी और क्या किन्हीं बीच में आ पड़ने वाली परिस्थितियों के कारण वह स्वीकृति अब रद्द कर दी गई है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह सम्भव हो सकता है कि सभा सचिव की श्री फिज़ों के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप वह नागालैंड प्रशासन से बातचीत करने के लिये सहमत हो गया हो ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रश्न "सहमत हो गया हो" का नहीं है, यह प्रश्न तथ्यों का है। क्या सरकार यह दावा करती है अथवा यह नहीं जानती कि उसके एक सभा सचिव ने वास्तव में फिजो के साथ बातचीत की थी। "सहमत हो गया होगा" का प्रश्न कहां है। हम स्पष्ट रूप से यह जानना चाहेंगे कि क्या वह उसके साथ सहमत हुए थे अथवा नहीं ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमन्

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रधान मंत्री चाहें तो वह बैठ कर उत्तर दे सकते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

अध्यक्ष महोदय : सदन की यह इच्छा है कि मैं उनसे बैठकर उत्तर देने के लिये प्रार्थना करूं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमन्, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं । जब मैं इसकी आवश्यकता अनुभव करूंगा तो वैसा ही करूंगा ।

Shri Raghunath Singh : At times one should meet the Speaker's wish.

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह तो नहीं जानता कि ठीक क्या बातचीत हुई थी, परन्तु यह सम्भव है कि नागालैंड सरकार के साथ इस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए उसको संसद सचिव ने सुझाव दिया हो ।

श्री हरिविष्णु कामत : क्या मैं प्रधान मंत्री को उनके उस वक्तव्य की याद दिला सकता हूं जो कि उन्होंने पिछले सत्र में, या तो किसी प्रश्न के उत्तर में अथवा आधे घंटे की चर्चा के दौरान दिया था और जिसका आशय यह था कि श्री फिज़ो, प्रकट रूप से अथवा गुप्त रूप से, यदि चीन से भी नहीं तो पाकिस्तान से हथियार प्राप्त कर रहे हैं, और यदि ऐसी बात है तो क्या भारत सरकार की नीति एक ऐसे व्यक्ति को सब प्रकार की सुविधायें देने की है जिसकी कि हमारे एक अथवा दोनों ही वर्तमान शत्रुओं के साथ सांठगांठ है और जो हमारे देश का इतना घोर देशद्रोही है ?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : कुछ नागाओं के सम्बंध में यह बात सच है कि वे पाकिस्तान से हथियारों के रूप में और प्रशिक्षण के रूप में सहायता लेने का प्रयत्न करते रहे हैं । परन्तु जहां तक श्री फिज़ो का सम्बंध है वह इस समय भारत से बाहर हैं, जैसा कि सदन को ज्ञात ही है, और उनके भूतकालीन कार्यकलापों के बावजूद भी भारत सरकार ने यह सोचा कि यदि वह नागालैंड आना और वहां की वर्तमान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करना चाहें तो भारत सरकार मार्ग में रोड़ा नहीं अटकायेगी क्योंकि वह नागालैंड में शान्ति चाहती है । मुख्य बात तो यह है कि श्री फिज़ो को यहां ऐसी वर्तमान स्थिति में आना है जब कि वहां कोई राचीनक परिवर्तन करना सम्भव नहीं है । नागालड की हमने एक विशेष स्थिति रखी है । उसे पूर्ण स्वायत्त दिया गया है, वह एक पूर्ण राज्य है और वहां के लोगों को उस क्षेत्र के शासन में भाग लेने का पूरा मौका है । इस स्थिति में यदि श्री फिज़ो वहां आना चाहें और मुख्य मंत्री तथा अन्य लोगों के साथ बातचीत करना चाहें तो भारत सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे देगी । यदि श्री फिज़ो यहां पर नहीं आना चाहते हैं तो जैसा वह चाहते हैं वैसा प्रसन्नता से करें । यह निश्चय करना तो उनका काम है कि वह यहां पर आना चाहते हैं अथवा नहीं ।

Shri Yashpal Singh : Mr. Phizo had gone to England without the permission of this powerful Government. Could the Government inform about the action taken against the fugitive and shelter being given to him ?

Mr. Speaker : This question does not arise at this moment.

Shri Yashpal Singh : Sir, I may be allowed to ask another question. Why are negotiations going to be held with Mr. Phizo when cases are standing against him ? How can the Nagaland Government give permission to a person who is a culprit in the eyes of the Central Government ?

Mr. Speaker : The Hon. Member is entering into discussion and not asking a question..

श्री स्वैल : वैदेशिक कार्य मंत्री ने अभी अभी बताया है कि नागालैंड के मुख्य मंत्री की प्रार्थना पर भारत सरकार इस बात से सहमत हो गयी है कि यदि श्री फिज़ो भारत आने और मुख्य मंत्री के साथ बातचीत करने का निश्चय करते हैं तो उन्हें सुरक्षादान दिया जायेगा । क्या मैं प्रधान मंत्री महोदय

से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने नागालेंड के मुख्य मंत्री और श्री फिज़ो को खुली छूट दे रखी है। क्या उस क्षेत्र में शांति बनाये रखने के हित में वे उन पर कोई शर्तें नहीं रखना चाहते ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो बात माननीय सदस्य जानना चाहते हैं वह बिल्कुल स्पष्ट है। हम ऐसी कोई शर्त नहीं रखना चाहते जो कि स्वयं नागालैंड सरकार ने ही नहीं रखी है। नागालैंड सरकार और भारत सरकार इस मामले में बिल्कुल एक हैं। श्री फिज़ो को यह बता दिया गया था कि वह यहां पर नागालैंड सरकार की प्रार्थना पर और नागालैंड सरकार द्वारा रखी गई शर्तों पर ही आयेंगे ।

श्री ज० ब० सि० बिष्ट : क्या मैं जान सकता हूं कि नागालैंड में आने का यह प्रस्ताव कब तक बना रहेगा ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

Shri Bibhuti Mishra : The reply first given by the Government indicates that a suggestion was given by the Nagaland Government and it was accepted by the Centre. May I know whether Government, while entering into negotiations with Phizo has kept in view the violent activities of Phizo or his accomplices when he was in India ?

Shri Jawaharlal Nehru : It must have been kept in mind but I do not know whether he should go there and have talks in this regard.

श्री नाथ पाई : एक ऐसी विचारधारा फैल रही है कि भारत सरकार की अपनी यह धारणा है कि श्री फिज़ो के साथ समझौता किये बिना नागालैंड में चरम और अन्त्य शांतिस्थापन सम्भव नहीं है। यह विचारधारा किस हद तक ठीक है ? यदि यह विचारधारा सही है तो क्या मैं जान सकता हूं कि जब भारत सरकार ही बातचीत करना चाहती है तो फिर वे प्रधान मंत्री के संसद सचिव के माध्यम से बातचीत करने का छल कपट क्यों कर रहे हैं और उस राज्य सरकार की सहायता करने की बात की आड़ क्यों ले रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू उठे ।

श्री त्यागी : कृपया बैठ कर ही उत्तर दें। श्रीमन्, हम उन्हें क्लान्त नहीं करना चाहते।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह मेरे लिए अच्छा है ।

श्री हरिविष्णु कामत : हमने उनसे एक बार प्रार्थना की है। अध्यक्ष महोदय ने भी उनसे प्रार्थना की है। इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं ? हम उन पर जोर तो नहीं डाल सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि वह अपने को क्लान्त न करें क्योंकि मुझ से केवल संसद सदस्यों ने ही नहीं अपितु बाहर के व्यक्तियों ने भी यह कहा है कि मैं उनसे यह प्रार्थना करूं कि वह खड़े हो कर अपने को क्लान्त न करें।

श्री त्यागी : क्या वह सदन की भावनाओं का आदर करने की बात को भूल गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य का यह विश्वास, अथवा यदि मैं ऐसा कह सकता हूं तो यह आक्षेप, बिल्कुल गलत है कि भारत सरकार का यह विचार है कि श्री फिज़ो की सहायता के बिना नागालैंड में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता । यह बिल्कुल ही गलत है। परन्तु भारत सरकार अब भी यह समझती है कि ऐसी बहुत सी बातें की जा सकती हैं जिनसे कि नागालैंड में पूर्ण शान्ति तथा व्यवस्था शीघ्र स्थापित की जा सके । अन्यथा, इसमें कुछ अधिक समय लगेगा। जहां तक संसद सचिव के जाने और श्री फिज़ो से मिलने का सम्बंध है, मैंने उनसे श्री फिज़ो से मिलने के लिए नहीं कहा। वह वहां पर गये और उस से मिले और मैं समझता हूं कि ऐसा उसने ठीक ही किया ।

श्री हरिविष्णु कामत : परन्तु आपको कोई आपत्ति नहीं हुई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमको कोई आपत्ति नहीं हुई, निश्चय ही नहीं। नागालैंड के मुख्य मंत्री द्वारा जो उत्तर भेजा गया था वह इसकी हमारी पूर्व जानकारी के बिना ही भेज दिया गया था। परन्तु बाद में हमें जानकारी मिल गई थी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या भारत सरकार यह जानती है कि श्री फिज़ो किन प्रश्नों पर नागालैंड सरकार से बातचीत करना चाहते हैं ? क्या यह केवल शांति और व्यवस्था बनाये रखने से ही सम्बंधित है, जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी कुछ मिनिट पहले ही कहा था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्री फिज़ो के विचार में क्या बात है यह हम नहीं जानते।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि सुरक्षा दान देते समय क्या श्री फिज़ो की भारत आने पर गतिविधियों के सम्बन्ध में कुछ शर्तें रखी गई थीं जिससे कि यहां पर और उपद्रव खड़ा करने से उन्हें रोका जा सके ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : वह यहां पर नागालैंड सरकार के साथ बातचीत करने के निश्चित उद्देश्य से आ रहे हैं और केवल यह शर्त रखी गई है कि बातचीत विद्यमान राचनिक व्यवस्था तक ही सीमित होगी।

आकाशवाणी के लिये नया ट्रांसमीटर

+

*१२४. श्री महेश्वर नायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री श० न० चतुर्वेदी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हेम बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कछवाय :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री केप्पन :
श्री ह० मधुसूदन राव :
श्री हरिविष्णु कामत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के मिथ्या प्रचार को निष्प्रभावी बनाने के लिये आकाशवाणी में एक नया ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है ;

(ख) इस ट्रांसमीटर की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) क्या आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर ली गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) चीन के मिथ्या प्रचार को निष्प्रभावी बनाने के लिये पर्याप्त शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत १ करोड़ रुपये है ।

(ग) वित्त मंत्रालय ने ट्रांसमीटर का रुपया भुगतान देशों से खरीदने के लिये स्वीकृति दे दी है ।

श्री महेश्वर नायक : हम यह उपकरण किस देश से खरीदेंगे तथा वी०ओ०ए० सौदे के मुकाबले इस सौदे के क्या लाभ हैं ?

श्री शामनाथ : हमें रुपया भुगतान देशों से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं—एक चैकोस्लोवाकिया से तथा दूसरा हंगरी से ।

श्री महेश्वर नायक : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वी० ओ० ए० सौदे के मुकाबले इस सौदे में हमें कोई लाभ है ।

श्री शामनाथ : अवश्य श्रीमान् । जब हमारे अपने ट्रांसमीटर्स होंगे, तो वी० ओ० ए० सौदे में जो शर्तें थीं, वे नहीं होंगी ।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार के लिये विदेश से इस प्रकार का उपकरण प्राप्त करना कब तक सभव हो सकेगा ?

श्री शामनाथ : हमें जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, हम ने उन्हें संभरण विभाग के पास जांच पड़ताल के लिये भेज दिया है । चैकोस्लोवाकिया के पास चार चार सौ किलोवाट वाले २ ट्रांसमीटर हैं जो तत्काल मिल सकते हैं । यदि संभरण विभाग प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कर ले तो हम इन दोनों को ४–५ महीनों में प्राप्त कर सकते हैं ।

Shri Sidheshwar Prasad : Considering the necessity of transmitters as of utmost importance would Government try to get these transmitters as soon as possible and more specially finalisethe negotiations which are going on with Czechoslovakia?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : We are trying to get those transmitters as early as possible. If possible our effort would be to complete the work in four or five months. As has been stated by the hon. Deputy Minister, the transmitters are readily available but they are of 400 Kwts. each. If both of them are combined, we can have one transmitter of 800 Kwts. and that will serve our purpose. But it would be better if we can get a transmitter of 1,000 Kwts. and we are trying for it.

Shrimati Renu Chakravartty : It was said on an earlier occasion that it would not be available.

Shri Bibhuti Mishra : I want to know which of the two transmitters, one about which there was a deal with U.S.A. and the other about which negotiations are going on with Czechoslovakia, is more powerful. Who can give us a transmitter as powerful as the one offered by U.S.A. ?

Shri Satya Narayan Sinha : It is difficult to estimate its power. We judge it from Kilowatts only. If it is of 1000 Kwts., it will be equal to that. I cannot go into technical details as to which one will be more powerful but one of 800 Kwts. would necessarily be weaker than that of 1000 Kwts.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : वी० ओ० ए० सौदे पर जो वाद-विवाद उत्पन्न हुआ था, जो कि अन्य कारणों में से एक कारण था, उसके अतिरिक्त और क्या कारण थे जिस से ट्रांसमीटर प्राप्त करने में विलम्ब हुआ ?

श्री सत्य नारायण सिंह : वी० ओ० ए० सौदे में जो कुछ हुआ, वह बिल्कुल स्पष्ट है । परन्तु उस समय विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं थी । हमने अब वित्त मंत्रालय को राजी कर लिया है और अन्ततः वह इस के लिये तैयार हो गया है कि इस को सर्वोच्च पूर्वता प्रदान की जाये । अतः अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

श्रीमती सावित्री निगम : इन दो छोटे ट्रांसमीटरों के प्राप्त हो जाने के बाद, हमारी आवश्यकता का कितना भाग पूरा हो जायेगा ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम एक १,००० किलोवाट का ट्रांसमीटर प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु यदि हमें ये दोनों भी प्राप्त हो जायें और हम इन दोनों को मिला कर ८०० किलोवाट का बनालें, तो भी हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Now when the agreement with VOA has been revoked and India's prestige has suffered on that account, is Government in a position to tell who has been at fault in entering into this agreement which ultimately led to its revocation ?

Mr. Speaker : It is not necessary to tell now.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चीन के मिथ्या प्रचार को निष्प्रभावी बनाने हेतु किन मुख्य भाषाओं के लिये यह ट्रांसमीटर प्रयोग में लाया जायेगा ? ट्रांसमीटर लगाने से पहिले ही, क्या सरकार ने इस के लिये कोई कदम उठाये हैं कि उन देशों की आवश्यक भाषाओं में प्रसारण करने के लिये पर्याप्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिया जाये ताकि देरी न हो ?

श्री सत्य नारायण सिंह : अवश्य, प्रारम्भ करने से पहिले वे कदम उठाये जायेंगे . . .

श्री नाथ पाई : क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या हम कर्मचारियों को अभी से प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि ट्रांसमीटर लगते ही हम उन भाषाओं में प्रसारण कर सकें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रसारण किन किन भाषाओं में किया जायेगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं भाषायें तत्काल नहीं बता सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या उन में बंगाली भी है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : बंगाली के बारे में मुझे पता नहीं है परन्तु मेरा विचार है कि हिन्दी अवश्य है । फिर भी मैं पता लगाऊंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दूसरे देशों के व्यक्ति बंगाली अथवा हिन्दी नहीं बोलते हैं । माननीय मंत्री जी हमें यह बताये कि यह ट्रांसमीटर किन किन भाषाओं के लिये प्रयोग में लाया जायेगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : ट्रांसमीटर विदेशों में प्रसारण करने के लिए होगा और स्वभावतया प्रसारण दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका के देशों की भाषाओं में होगा । हमें उन भाषाओं में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है । अन्यथा बंगाली और हिन्दी में प्रसारण करने का कोई अर्थ नहीं है जिस को उन देशों के व्यक्ति नही समझ सकते ।

श्री नाथ पाई : यह तो पूर्णतया स्पष्ट और सामान्य बुद्धि की बात है कि ये प्रसारण उन देशों की भाषाओं में ही करने पड़ेंगे । हम तो भाषायें जानना चाहते हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : १,००० किलोवाट के ट्रांसमीटर को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : अवश्य, जैसा मैंने कहा, हम प्रयत्न कर रहे हैं । नहीं तो ८०० किलोवाट का ट्रांसमीटर तो उपलब्ध है ही ।

Shri Vishram Prasad : It has been a year since China launched her aggression and an agreement was signed with VOA. May I know whether the Government would purchase the proposed transmitter when China attacks us a second time or before that ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

टस्कर परियोजना

\+

*१२५. श्री यशपाल सिंह :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री उमानाथ :
श्री हेमराज :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री दिनांक १८ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ आसाम की टस्कर परियोजन (अब वर्तक) में लगे हुए कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) डिब्रूगढ़ की टस्कर परियोजना (अब वर्तक) में भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में जांच अभी भी चल रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : What action has been taken against officers guilty of making payments for those roads which exist only on paper and have not been actually constructed ? How many of them have been arrested and how many are still unpunished ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : डिब्रगढ़ रियोजना के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच कुछ अन्य विषयों से सम्बन्ध रखती है, माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लख किया है उससे नहीं ।

Shri Yashpal Singh : What part of the amount embezzled in this project has been traced by the Government ?

Shri Y. B. Chavan : If a separate question is asked about it, I can give a reply.

Shri Ram Sewak Yadav : When will this report be received ? What are the revelations made by the enquiry conducted so far and who have been found responsible for all this ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : एक जांच और हुई थी जोकि तेजपुर के बारे में थी । कुछ मुकदमे अभी चल रहे हैं परन्तु यह नवीनतम जांच है जोकि गत वर्ष के मध्य में किसी समय शुरू हुई थी, ब्यौरे में जाने से और जांच की आवश्यकता पड़ी ।

श्री भागवत झा आजाद : चूंकि संसद् सदस्यों के दो दल वहां किये गये बहुत अच्छे कार्य को देख आये हैं, अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह जांच आपातकाल के दौरान वहां के कर्मचारियों द्वारा किये गये व्यवहार से सम्बन्ध रखती है अथवा धन के गबन से अथवा इस प्रकार की चीजों से ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आक्रमण के दौरान उनके व्यवहार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह उनके सामान्य कार्य के बारे में थी ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी । जांच के दौरान क्या कोई गिरफ्तारियां की गई हैं अथवा सौदे में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाई की गई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अन्य मामलों में गिरफ्तारियां की गई हैं तथा मुकदमे चल रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या विभाग के कुछ अधिकारियों को निलम्बित किया गया है ? पुलिस ने कितने अधिकारियों पर मुकदमा चलाया है ?

श्री यशवन्तराव : चह्वाण मेरा विचार है कि ४ अधिकारी निलम्बित किये गये हैं. परन्तु इस मामले में नहीं । इस मामले में जांच अभी भी चल रही है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस व्यापक धारणा का कोई आधार है कि "टस्कर" नाम बदल कर अब "वर्तक" इसलिए रखा गया है क्योंकि पहिले "टस्कर" शब्द का उच्चारण "तस्कर" हो जाया करता था जिस का हिन्दी में अर्थ होता है "चोर अथवा लुटेरा" ? "टस्कर" से बदलकर "वर्तक" नाम रखने का क्या कारण है ?

श्री त्यागी : यह अंग्रेजी में "टस्कर" है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : नाम में परिवर्तन दिये गये अनेक सुझावों के कारण किया गया था । यहां सभा में भी सुझाव दिये गये थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह कब हुआ था ?

श्री पं० वेंकटा सुब्बया : इस बात को देखते हुए कि टस्कर परियोजना के कार्यकरण के बारे में सीमावर्ती क्षेत्रों में बुरा प्रभाव पड़ा है। क्या सरकार सारी व्यवस्था को पुनर्गठित करने तथा अपने कार्यकुशल इंजीनियर वहां नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ताकि कार्य शीघ्रतापूर्वक हो सके ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मेरा विचार है कि कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है।

MANUFACTURE OF SUPERSONIC AIRCRAFT

\+

126. **Shri Prakash Vir Shashtri :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Sarjoo Pandey :
Shrimati Savitri Nigam
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Maheswar Naik :
Shri Kapur Singh :
Shri Solanki :
Shri P. H. Bheel :
Seri HimmatSinhji :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri P. C. Borooah :
Shri P. K. Ghosh :
Shri J. B. S. Bist :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri D. C. Sharma :
Shri S. M. Banerjee :
Shri P. R. Chakravati :
Shri D. J. Naik :
Shri Koya :
Shri M. Rampure :

Will the Minister of **Defence**— be pleased to state :

(a) whether any satisfactory progress has been made in the manufacture of supersonic aircraft ;

(b) whether it is a fact that the progress in manufacture of MIG aircraft is very slow ;

(c) whether India has asked for permission from Russia for the manufacture of MIG-24 aircraft ; and

(d) if so, the Russian reply thereto ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). आयोजना के आकार और उस से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में मिग विमानों के लिए उत्पादन सुविधाओं के स्थापन-कार्य में, सन्तोषजनक प्रगति हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Prakash Vir Shastri : Keeping in view the necessity of supersonic aircraft, is Government considering any scheme for the manufacture of such aircraft with the collaboration of any other country besides Russia ?

श्री रघुरामैया : किसी अन्य देश के साथ बातचीत नहीं की गई है। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में एच० एफ० २४ का विकास कर रहे हैं। जोकि एक अतिस्वन विमान भी है तथा "औरफियस" इंजिन द्वारा चालित इसके "मार्क आई सीरीज़" का शस्त्रास्त्र परीक्षणों सहित विभिन्न प्रकार से परीक्षण किया जा रहा है। हमें आशा है कि यह शीघ्र ही संवृन्द सेवा[1] के लिये उपलब्ध हो जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the time-limit fixed by Government for the manufacture of MIG planes and the progress made therein so far, is Government in a position to state whether the manufacture of these planes would commence within the fixed time ?

श्री रघुरामैया : यह एक जटिल परियोजना है क्योंकि इसमें विमानों के ढांचे तथा इंजनों के निर्माण का प्रश्न ही अन्तर्गस्त नहीं है अपितु "मिसाइल" का भी प्रश्न है। परियोजना में प्रतिवदनों में से एक प्रतिवदन अभी भी प्राप्त होना है। अतः यह अनुमान लगाना कि यह समूचा एकक अमुक तिथि तक पूरा कर दिया जायेगा बहुत कठिन है।

श्री हेडा : एक बार हमें बताया गया था कि इसका निर्माण कोरापुट तथा नासिक में किया जायेगा। अब हमें यह बताया गया है कि निर्माण के लिये अन्य स्थान भी चुन लिये गये हैं। विभिन्न स्थान कौन से हैं तथा वहां पर किन विभिन्न भागों का निर्माण किया जायेगा ?

श्री रघुरामैया : वस्तुतः "गाइडिड मिसाइल" के इलेक्ट्रोनिक पुर्जों के लिये एक और स्थान हैदराबाद चना गया है। कोरापुट में इंजिन का तथा नासिक में विमान के ढांचे का निर्माण होगा।

मैं सभा की जानकारी के लिये यह बता दूं कि विमानों के निर्माण में यह आम बात है कि इंजिनों का निर्माण एक स्थान पर हो तथा विमानों के ढांचे का दूसरे स्थान पर।

Shri Onkar Lal Berwa : In view of the fact that Russia's permission has been sought for manufacturing the first MIG plane, I want to know whether there is any agreement that we will have to seek their permission when manufacturing it.

श्री रघुरामैया : वह शस्त्रास्त्र तथा युद्धोपकरण के बारे में है। यह मिग अतिस्वन विमानों के बारे में है।

श्री नाथपाई : क्या यह सच है कि मिग विमानों के निर्माण के बारे में जो आशा दिलाई गई थी तथा प्रचार किया गया था उसके बावजूद सत्यता यह है कि रूपरेखा को अन्तिम रूप देने में तनिक भी प्रगति नहीं हुई है और अब यह महसूस किया गया है कि जो भी रूपरेखा है वह भारत की प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है और यदि हां तो हमारी सरकार द्वारा किये गये परिवर्तन प्रस्तावों पर रूस की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री रघुरामैया : जानकारी पूर्णतया गलत है। **(अन्तर्बाधाएं)**। परियोजना प्रतिवेदन यथावत् प्राप्त हो गये हैं तथा उनकी जांच हो रही है। हम आग बढ़ रहे हैं।

श्री हरिविष्णु कामत : परन्तु शिथिलता से काम हुआ है।

श्री नाथ पाई : क्या मैं यह समझूं कि वास्तविक उत्पादन के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री जी द्वारा सभा को बताये गये निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगित हो रही है ? उन्होंने उस भाग का उत्तर नहीं दिया है ?

[1] squadron service.

श्री रघुरामैया : नासिक कारखाने में असैनिक निर्माण-कार्य चालू हो गया है। कोरापुट में इंजिन कारखाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन एक जटिल चीज है। क्योंकि इसमें आर० डी० ९ एफ एफ० इंजिन की बात भी सम्मलित है। परियोजना प्रतिवेदन की तकनीकी दृष्टि से पुन: जांच हो रही है। परियोजना प्रतिवेदनों में से एक प्रतिवेदन हाल में ही प्राप्त हुआ है। इस में हुये परिहार्य विलम्ब के बारे में मुझे पता नहीं है।

श्री प्र० के० दे : चूंकि इन विमानों के बनाने में इतना अधिक समय लगता है, अत : क्या हमें इस बात का आश्वासन दिया जा सकता है कि जब तक इनका उत्पादन चालू होगा, तब तक ये गत-प्रयोग नहीं होंगे ?

श्री रघुरामैया : गतप्रयोग होना एक शेष बात है जो किसी भी विमान पर लागू हो सकती है परन्तु हमारी कोशिश यही रहेगी कि निर्माण करते करते अपनी तकनीकी जानकारी के अनुसार इसमें आवश्यक रूपभेद करते जायें।

श्री जोकीम आलवा : माननीय मंत्री जी ने बताया कि अन्य किसी के साथ कोई बातचीत नहीं की गई। क्या अतिस्वन विमानों के यहां निर्माण के लिये पश्चिमी देशों में से किसी देश से, विशेषकर अमरीका अथवा फ्रांस से, कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ?

श्री रघुरामैया : मिग सौदे के बाद से ? जी, नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : वायु सेना सहित हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिये अकरीका की सरकार द्वारा बार बार दिये गये आश्वासनों को देखते हुए, क्या हमारी सरकार ने उससे कोई प्रार्थना की है कि वह अतिस्वन विमानों के निर्माण में हमारी सहायता करे ?

श्री रघुरामैया : अपने निर्माण कार्यक्रम में सहयोग के लिये हमने कोई प्रार्थना नहीं की है।

Shri Yashpal Singh : Government had stated that 6 factories would be set up forthe manufacture of supersonic aircraft and they would be turned in to ordnance factories. I want to know how many of them are ready to be Commissioned, how many have started the work and in how many work is yet to start.

श्री रघुरामया : समझौते में यह व्यवस्था है कि हमारा उत्पादन-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चले।

हिन्द महासागर में सातवां अमरीकी समुद्री बेड़ा

+

श्री भागवत झा आजाद :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास
श्री विभूति मिश्र :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री गो० महन्ती :
श्री बी नेन भट्टाचार्य :

*१२७. डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री उमा नाथ :
श्री वारियार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नम्बियार :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री ह० च० सोय
श्री विश्व नाथ पांडेय :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने श्री टेलर के भारत के दौरे के पश्चात्, हिन्द महासागर में गश्त लगाने वाले सातवें अमरीकी समुद्री बेड़े के संबंध में भारत सरकार से परामर्श किया है और कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) स्थिति वैसी है जैसी कि २१-१२-१९६३ को राज्य सभा में प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताई थी। हिन्द महासागर में गश्त लगाने वाले सातवें अमरीकी बेड़े के संबंध में अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को अपने अभिप्राय के बारे में कोई निर्णय नहीं भेजा है।

(ख) भारत सरकार की प्रतिक्रिया पहले ही प्रधान मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिये गये वक्तव्य में, जिसका जिक्र पैरा (क) में ऊपर किया गया है, स्पष्ट कर दी गई है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या भारत सरकार का ध्यान इन्डियन एक्सप्रैस में कुछ समय पहले छपे इस समाचार की ओर गया है कि रूस सरकार हिन्द महासागर में गश्त करने वाले सातवें अमरीकी बेड़े का पीछा करने के लिये अपना अण अस्त्र का बेड़ा भेजने का विचार कर रही है, और यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इससे शीत युद्ध के क्षेत्र में कहां तक वृद्धि होगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हम ने यह समाचार सुना है।

श्री भागवत झा आजाद : हम जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। क्या भारत सरकार ने रूस सरकार से इस संबंध में कहा है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, नहीं।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवारलाल नेहरु) : मैं कुछ समझ नहीं पाया।

जवाहरलाल

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या हम ने रूस सरकार से कहा है (**अन्तर्बाधा**)

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न यह है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि रूस सरकार हिन्द महासागर में सातवें अमरीकी बेड़े का पीछा करने के लिये अपना बेड़ा भेजने का विचार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने यह समाचार नहीं देखा है । यह एक गलत समाचार मालूम होता है ।

श्री भागवत झा आजाद : यह समाचार भुवनेश्वर के अधिवेशन के समय इंडियन एक्सप्रेस में छपा था कि रूस सरकार बेड़ा भेजना चाहती है । खैर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस देश की प्रतिक्रियाएं, जो इस सम्बन्ध में बहुत तीव्र हैं, अमरीकी सरकार को बताई हैं कि उनकी इस प्रकार की कार्यवाही से दोनों देशों में व्याप्त परस्पर मित्रता और सौहार्द की भावना को आघात पहुंचेगा ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमारी प्रतिक्रियाएं सुज्ञात हैं क्योंकि संसद् और इसके बाहर उस पर चर्चा हुई है । इसके अतिरिक्त क्या किया गया, मुझे मालूम नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने कुछ समय पूर्व यह कहा था कि चीन की नौसेना के पास ऐसी पनडुब्बियां अथवा अन्य समुद्री जहाज हैं जो बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर में हमला कर सकते हैं, यदि हां, तो हमारी सरकार ने ऐसे संभाव्य आक्रमणों के विरुद्ध बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर की निगरानी करने के लिये क्या उपाय किए हैं अथवा कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले हमें हिन्द महासागर की निगरानी करनी चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : हम निगरानी नहीं कर सकते । क्या हमारे पास कोई उपाय हैं । क्या हमारे पास कोई चीज है क्योंकि प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के पास अब पनडुब्बियां हैं । उन्होंने ऐसा कहा । क्या हमारे पास चीन की पनडुब्बियों के विरुद्ध समुद्र की निगरानी करने के लिए पनडुब्बियां हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात की ओर आ रहे हैं । एक दूसरा प्रश्न है जो पनडुब्बियों से भी सम्बन्ध रखता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : हो सकता है हम उस प्रश्न तक न पहुंच सकें । कृपया इसका उत्तर देने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए पर्याप्त औचित्य होना चाहिए ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह लोक हित में है । भारत प्रतिरक्षा नियमों और देश की सुरक्षा के संबंध में इसका बड़ा महत्व है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । श्री स्वैल ।

श्री स्वैल : क्या सरकार का ध्यान लंका के प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य की ओर गया है कि लंका अपनी समुद्र सीमा में से किसी अणु अस्त्र वाले जहाज को नहीं गुजरने देगी और यह देखने पहल करेगी कि तटस्थ राष्ट्रों का कोई भी ऐसा जपाज लंका की समुद्र सीमा में न घुसे ? क्या ारत सरकार लंका की इस बात से सहमत है ?

श्री जवाहर लाल नहरू : मैं सहमत होने के बारे में नहीं जानता, परन्तु कोई ऐसा विदेशी जहाज हमारी समुद्र सीमा में नहीं आ सकता । यदि आएगा तो हम उस पर निश्चय ही आपत्ति उठायेंगे ।

श्री त्यागी : तो क्या मैं यह समझूं कि यह सातवां समुद्री बेड़ा जो हिन्द महासागर में गश्त लगाएगा हमारी समुद्र सीमा में नहीं घुसेगा ? क्या ऐसा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बिल्कुल यही कहा है । श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री इद्रजीत गुप्त : भारत की घोषित नीति यह है कि इस देश में किसी वैदेशिक सेना का अड्डा न बने । तो क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है कि हमारे समुद्र तटों के निकट एक विदेशी नौ सेना के बेड़े की उपस्थिति चाहे वह परमाणु हथियारों से लैस हो या नहीं, आधुनिक युद्ध की परिस्थितियों में, हमारी समुद्र सीमा में सैनिक अड्डा होने के समान है । यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है, और क्या अमरीकी सरकार को इससे अवगत करा दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि यह समद्र में सैनिक अड्डे होने के समान है ।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के ऐतिहासिक विभाग ने सरकार को यह सलाह दी है कि १५वीं शताब्दी की प्रथम दशाब्दी में चिना हो नाम के एक चीनी दरबारी ने सम्राट के नाते हिन्द महासागर पर पूर्ण स्वामित्व जमा लिया था और भारत से नजराना लिया करता था, यदि हां तो क्या सरकार ने हाल ही में चीनी पनडुब्बियों के हमारे समुद्र में आने की पृष्ठ भूमि में अमरीका के सातवें बेड़े के प्रश्न पर विचार कर लिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इस प्रश्न के उत्तर की आशा रखते हों ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री नाथ पाई : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि भारत के पास हिन्द महासागर की निगरानी करने के लिए अच्छा बेड़ा होता तो यहां आने के लिए कोई भी विदेशी बेड़ा प्रलोभित नहीं होता, क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे समद्र की निगरानी करने के लिये हम ऐसे बेड़े के प्रतिबिम्ब की भी कब आशा कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल भिन्न बात है ।

Shri Bibhuti Mishra : Has the Government of India, in consultation with the countries adjacent to the Indian Ocean, such as Burma, Ceylon, Malaysia, Indonesia, decided that these countries should send a joint protest letter to the U.S.A. saying that their 7th fleet should not operate in the Indian Ocean ?

Shri Jawaharlal Nehru : No.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या भारत सरकार भारतीय समुद्र सीमा के परे आने वाले बेड़े को वहां न आने के लिये, अपनी इच्छा प्रकट कर सकती है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं स्थिति को स्पष्ट करने के लिये प्रधान मंत्री द्वारा पहले दिए गए वक्तव्य के कुछ वाक्य पढ़ कर सुनाता हूं ।

"भारतीय समुद्र सीमा से परे का समुद्र अन्य देशों के नौसेना जहाजों की भांति अमरीका की नौसेना के जहाजों के लिये भी खुला है । यह कहना सर्वथा गलत है कि हिन्द महासागर में कुछ जहजों

पोत विहार से स्वतन्त्रता अथवा तटस्थता की नीति को भय है। तथापि शंकाओं को दूर करने के लिए मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि हम अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी के लिए मित्र देशों से सहर्ष सहायता प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु कोई विदेशी जहाज देश की वास्तविक प्रतिरक्षा में भाग नहीं ले सकता। यह प्रतिरक्षा तो केवल भारतीय सशस्त्र सेना और देश के लोगों द्वारा ही की जाएगी।"

तटस्थ देशों का सम्मेलन

+

*१२८. श्री भागवत झा आजाद :
श्री श्री नारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सं० च० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सरजू पांडेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री उमानाथ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नाथ पाई :
श्री कजरोलकर
श्री शशिरंजन :
श्री हेमराज :
श्री अंजनप्पा
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) किन किन देशों को निमंत्रित किया जा रहा है ; और

(ग) क्या कोई निश्चित कार्यावलि परिचालित की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). भारत सरकार ने राष्ट्रपति नासर और प्रधान मंत्री श्रीमती भंडारनायके की १३ अक्तूबर, १९६३ की संयुक्त विज्ञप्ति का स्वागत किया है जिसमें कि वे इस बात पर राजी हो गए हैं कि तटस्थ देशों का एक दूसरा सम्मेलन होना चाहिये। प्रस्तावित सम्मेलन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री और सम्बन्धित

देशों के प्रमुखों के बीच पत्र व्यवहार हुआ है। पत्र व्यवहार में किए गए प्रस्ताव और सुझाव अन्तिम नहीं हैं और उन पर सभी सम्बन्धित देश विचार कर रहे हैं। ऐसा विचार है कि इस बात पर कि किन किन देशों को निमंत्रित किया जाय अथवा इसकी निश्चित कार्यावलि क्या होनी चाहिए, कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इन गैर सरकारी बातचीतों में सम्मेलन बुलाने के लिये कोई अनान्तिम समय निर्धारित किया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : किसी अन्य ब्योरों की अनुपस्थिति में, क्या यह निर्णय किया गया है कि सम्मेलन किस स्थान पर होगा ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं। स्थान और समय निश्चित नहीं किए गए हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह प्रस्तावित सम्मेलन अन्य सम्मेलन से, जो कि आशा है बेंडग के नमूने पर आयोजित किया जाएगा, किस तरह भिन्न होगा ?

श्री दिनेश सिंह : बेंडंग सम्मेलन तो अफ्रीका और एशिया के महाद्वीपों के देशों का एक अफ्रीकी-एशियायी सम्मेलन है। यह तटस्थ देशों का सम्मेलन है, उन देशों का सम्मेलन जिनका कि तटस्थता के सिद्धान्तों में विश्वास है।

श्रीमती सावित्री निगम : इस सम्मेलन में जिन देशों के भाग लेने की आशा है उनके नाम और संख्या क्या हैं ?

श्री दिनेश सिंह : कोई नाम निश्चित नहीं किए गए हैं। एक सामान्य प्रस्ताव है कि इस बात का निर्णय कि किन देशों को निमंत्रित किया जाएगा वे देश करेंगे जिन्होंने बलग्रेड सम्मेलन में भाग लिया था।

Shri Yashpal Singh : China has tried and has all along been trying to sabotage the Conference of Non-aligned countries. I want to know what action is being taken by our Government to foil the Chinese efforts.

Shri Dinesh Singh : Government is trying to hold such a Conference at an early date.

श्री इन्द्र जीत गुप्त : क्या सरकार का ध्यान "स्टेट्समैन" के कोलम्बो स्थित संवाददाता द्वारा भेजे गए इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि लंका में इस बात पर काफी रोष छाया हुआ है कि भारत ने इस सम्मेलन की तैयारी के सम्बन्ध में अपने एक मंत्री को प्रतिनिधि बना कर राष्ट्रपति नासर से मिलने भेजा न कि श्रीमती बन्द्रनायके से जो कि इस सम्मेलन की सहआयोजक हैं, यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : लंका की सरकार इस समाचार की ओर ध्यान नहीं देती। उसने स्पष्ट कर दिया है कि यह उसका दृष्टिकोण नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं कैरो अथवा बैलग्रेड में विशेषतः इस सम्मेलन के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं गया था। मैं वहां पर उनके निमंत्रण पर गया था और जब मैं वहां था तो यह बात चर्चा किए गए विषयों में से एक थी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि चीन सरकार इस सम्मेलन में किसी न किसी तरह से घुसने के लिये अफ्रीकी और एशियाई देशों पर बहुत जोर डाल रही है, यदि हां, तो क्या

2202 (Ai) LSD—3.

सरकार ने सभी संबंधित देशों को यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी ऐसे सम्मेलन में भाग नहीं लेगी जिसमें चीन सरकार का प्रतिनिधि होगा ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक इस सम्मेलन का संबंध है प्रधान मंत्री चाउनलाई ने कैरो में बिलकुल स्पष्ट रूप से कह दिया था कि चीन एक गुट वाला देश है और इस लिए उसके इस सम्मेलन में आने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know whether this Conference of Non-aligned countries would consider Chinese aggression, the territory under their possession and their refusal to accept the Colombo proposals.

Shri Dinesh Singh : It is felt that disputes between one country and another should not be settled in this Conference.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तटस्थता की कई किस्में हैं सक्रिय तटस्थता और निष्पक्ष तटस्थता, संबद्ध तटस्थता और असम्बद्ध तटस्थता और कुछ कृत्रिम तटस्थता भी—क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन में किन किन वर्गों के प्रतिनिधि आयेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आम भावना यह है कि जिन देशों ने बैलग्रेड सम्मेलन मे भाग लिया था उन्हें इस सम्मेलन में बुलाय जाए और फिर वे देश यह निर्णय करें कि किन किन और देशों को निमंत्रित किया जाना चाहिए ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether efforts are being made to hold this Conference in Delhi so that the Prime Minister could also easily participate in it?

Shri Dinesh Singh : The question about the venue of the Conference does not arise yet.

श्री स्वैल : क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन के प्रधान मंत्री, श्री चाउनलाई इस मास की २६ तारीख को लंका में होंगे, इसको ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि लंका को कुछ न कुछ रोष है, यद्यपि उपमंत्री का यह कहना है कि लंका को रोष नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि लंका के साथ हमारे संबंध में क्षति को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : इस बारे में कोई क्षति नहीं पहुंची है ।

नेफा में राजनैतिक सुधार

\+

*१२९. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बे० द० पुरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री उमानाथ :
श्री स्वैल :
डा० मा० श्री० अणे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में कुछ राजनैतिक सुधार किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच इस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री डा० एरिंग) : (क) और (ख). नेफा में लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं को मजबूत बनाने और विकास करने का प्रश्न बराबर सरकार के विचाराधीन है । हाल ही में इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव किये गये हैं जो अभी भी विचाराधीन हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : नागालड के लोगों के साथ घने सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार वही उपाय करना चाहती है जो नागालैंड में किये गये हैं ?

श्री डा० एरिंग : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या वहां पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता की राय जानने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री डा० एरिंग : यह सही है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब तक नेफा में दफतरशाही जोर शोर से चल रही थी, क्या सरकार के सामने स्वायत्तशासी ग्राम परिषदें बनाने की कोई योजना है जिस से कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके ।

श्री डा० एरिंग : जी, हां ।

श्री स्वैल : क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से छपे ८ जनवरी के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रधान मंत्री नेफा के संसद सदस्य द्वारा दिये गये इस प्रस्ताव पर राजी हो गये हैं कि प्रशासनिक सुधारों के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाय ?

बिना विभाग के मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : इस प्रकार की समिति नियुक्त करने के लिये राज्यपाल को मन्त्रणा दी गई है और मुझे आशा है कि वे शीघ्र ही ऐसा करेंगे ।

डा० मा० श्री० अणे : क्या नेफा में कुछ सुधार लागू करने के लिये संसदीय सचिव ने वैदेशिक-कार्य मंत्री को कोई पत्र लिखा है, यदि हां, तो वे सुधार क्या हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : संसदीय सचिव ने कोई विशेष सुझाव नहीं दिये हैं । सामान्य मामले पर चर्चा हुई और यह निर्णय किया गया कि मामले में अग्रेतर अध्ययन के लिये समिति की नियुक्ति आवश्यक है । जैसा कि मैं ने अभा सुझाया गवर्नर शीघ्र समिति की नियुक्ति करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन योजना

*१३०. श्री रा० गि० दुबे :
श्री महेश्वर नायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री प० कुन्हन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री सुरेंद्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन योजना लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा तोजना उपमंत्री (श्री च० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत दोनों निधियों के ऐसे सदस्यों की विधवा / नाबालिग बच्चों को, जो असमय मर जाते हैं २५ रु० मासिक की न्यूनतम परिवार पेंशन देने का विचार है ।

छात्रों के लिये सैनिक शिक्षा

*१३१. श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री कप्पन :
श्री शशि रंजन :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री हेम राज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेज के समस्त छात्रों के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई ;

(ख) अब तक कितने छात्रों के नाम दर्ज किये गये और १९६४–६५ में कितने छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण देने का विचार है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिये कितना धन व्यय किया जायेगा और इसमें केन्द्र और राज्यों को पृथक-पृथक कितना व्यय वहन करना होगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २२९८/६४]**

जम्मू तथा काश्मीर सीमा (कोटमेरा गांव) पर पाकिस्तानियों द्वारा छापा

*१३२. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हिम्मतसिंहजी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ दिसम्बर, १९६३ को जम्मू तथा काश्मीर राज्य के छम्ब क्षेत्र स्थित कोटमेरा गांव पर २० सशस्त्र पाकिस्तानियों ने छापा मारा ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस में उसने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या जम्मू तथा काश्मीर सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों ने जान और माल की रक्षा के हेतु रायफलें दिये जाने की मांग की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). जी, हां । २१ / २२ दिसम्बर, १९६३ की रात को लगभग १४ पाकिस्तानी जम्मू और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के परे से छम्ब क्षेत्र में खोर पुलिस स्टेशन के निकट एक दुकान को लूटने के अभिप्राय से कोटमेहरा गांव में घुस आये । अतिक्रमियों की सीमा पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, परन्तु वे लूटी हुई वस्तुओं को छोड़ कर बच निकाल । खोर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया हैं ।

(ग) हाल ही में सीमा के लोगों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । (जम्मू तथा काश्मीर की पहली सरकार ने सीमावर्ती लोगों को उनकी सुरक्षा के लिये शस्त्र दे रखे थे) :

भारतीय नौसेना के लिय पनडुब्बियां

*१३३. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प० कुन्हन :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौ सेना के लिये पनडुब्बियां खरीदने का है ; **और**

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय कर लिय गये हैं **तथा** यदि हां, तो क्या **निर्णय** किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

विदेशों से हथियार

*१३४. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियारों और उपकरण संभरण के लिये और अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को शक्तिशाली तथा आधुनिक बनाने के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण के लिए मित्र देशों के साथ कोई निश्चित करार अथवा संविदाएं की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २२९९/६४]**

सीमा विवादों का निबटारा

श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री मी० प्र० यादव :
श्री धवन :

*१३५. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को रूस की सरकार की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सीमा विवादों का निबटारा करने में शक्ति का प्रयोग न किये जाने संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय समझोतों के बारे में प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार की प्रतिक्रिया के संबंध में रूस को सूचित कर दिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मनन) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार रूस के प्रस्तावों से मुख्य रूप से सहमत है । भारत सरकार का कहना है कि किसी भी समस्या का समाधान शक्ति के प्रयोग से नहीं हो सकता और सभी सरकारों को सीमा विवादों के निबटारे के लिये शक्ति प्रयोग न करने पर राजी हो जाना चाहिये और राज्यक्षेत्रीय सीमाओं तक पीछे हट जाना चाहिये जो कि शक्ति के प्रयोग से बदल दी गई हैं। ऐसे समझौते से तनातनी दूर हो सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास बनाने में सहायता मिलती है जो कि सामान्य और पूर्ण निशस्त्रीकरण की संधि प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।

(ग) जी, हां ।

जंजीबार के भारतीय

*१३६. { श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अंजनप्पा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम राज :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री तन सिंह :
श्री केप्पन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री कोया :
श्री ईश्वर रेड्डी :

श्री गुलशन :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री द्वारका प्रसाद मौर्य :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जंजीबार में रहने वाले भारतीयों पर आक्रमण किया गया था और उनकी सम्पत्ति लूट ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का व्यौरा क्या है और संबंधित भारतीयों की किस सीमा तक हानि हुई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जंजीबार में १२ जनवरी, १९६४ को राज्य विप्लव हुआ । विधि और व्यवस्था सामान्य रूप से भंग हो गई और लूट खसोट और आग लगाने की घटनायें हुईं। भारतीय उद्भव के लोग उन में से थे जिन्हें जान और माल का नुक्सान पहुंचा। नुकसान की मात्रा का अभी पूरी तरह पता नही लगा है ।

चिनाकुरी कोयला खान

*१३७. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ जनवरी, १९६४ को चिनकुरी कोयला खान में खान २ का एक भाग बैठ गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ; और

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो इस के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख). छत के गिर जाने के कारण यह ११ जनवरी, १९६४ को एक दुर्घटना हुई जिसमे २ व्यक्ति मारे गये और एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुआ ।

(ग) जांच की गई । पता लगा कि एक शोरफायरर, जो कि खान का सरदार भी था और जिस स्वयं बड़ी चोट आई, दुर्घटना के लिये जिम्मेदार था ।

थुम्बा से राकेट छोड़ना

श्री नाथ पाई :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

*१३८. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री केप्पन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम के निकट थुम्बा में राकेट छोड़ने के स्थान से अब तक कितने राकेट छोड़े गये हैं ;

(ख) अब तक किये गये अध्ययन के परिणाम क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में भावी कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

बिना विभाग के मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) थुम्बा राकेट छोड़ने के केन्द्र से अब तक ७ राकेट छोड़े गये हैं ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २३००/६४] ।

भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण

*१३९. श्री यशपाल सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री नाथ पाई :
श्री शशि रंजन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा के गत सत्र के समाप्त होने के पश्चात विदेशी विमानों द्वारा कितनी बार भारतीय वायु सीमा का अतिलंघन किया गया ;

(ख) वे विमान किन देशों के थे ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार के अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार २१ दिसम्बर, १९६३ से अब तक अर्थात गत सत्र की समाप्ति से वायु सीमा का कई बार उल्लंघन हुआ है तीन बार पाकिस्तान द्वारा तथा एक बार चीन द्वारा।

(ग) सभी उल्लंघनों के बारे में विरोध पत्र भेज दिए गए हैं।

जनरल टेलर की यात्रा

*१४०. श्री महेश्वर नायक :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपालसिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री वारियर :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नम्बियार :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री ह० च० सोय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री गुलशन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने जनरल मैक्सवेल टेलर से उनकी भारत यात्रा के दौरान क्या बातचीत की ; और

(ख) क्या यह सच है कि उनकी यहां की गई यात्रा का एक परिणाम यह हुआ है भारतीय वायु सेना को अमरीकन अतिस्वन (सुपरसोनिक) विमानों से सुसज्जित करने का एक समझौत हो गया है ?

†प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जनरल टेलर किसी विशेष कार्य के लिए भारत नहीं आये थे मित्र देशों के सशस्त्र सेनाओं के उच्चाधिकारियों में आपस में मिलते रहने की सामान्य प्रक्रिया है। सेनाध्यक्ष जो जुलाई, १९६३ में अमरीका गये थे,

ने उनको भारत आने का निमंत्रण दिया था । भारत सरकार तथा जनरल टेलर में उसी प्रकार विचार विमर्श हुआ है जिस प्रकार मित्र देशों के सेनाध्यक्षों में होता है।

(ख) जी नहीं। इस संबंध में समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता है।

चीन द्वारा अतिक्रमण

*१४१. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :
श्री कोला वेंकैया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नाथ पाई :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारतीय राज्य-क्षेत्र का और अतिक्रमण किया है और अन्तिम रूप से कोलम्बो प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो नवीनतम स्थिति क्या है?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) भारतीय राज्य क्षेत्रों में कोई चीनी अतिक्रमण नहीं हुआ है। कोलम्बो प्रस्तावों के संबंध में चीनी सरकार की स्थिति के बारे में चीनी सरकार द्वारा लिए गए कदम में कोई परिवर्तन नही आया है । चीन यह दावा करता है कि उसने सिद्धान्ततः कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है जब कि प्रस्तावों के बारे में कुछ रिजर्वेशन भी बनाए हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार

*१४२. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्य **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद् के विस्तार के सम्बन्ध में अपने विचारों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का वास्तविक स्वरूप क्या है?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मनन) : (क) और (ख). भारत सरकार का विचार है कि संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी एशियाई देशों की सदस्य संख्या बढ़ जाने के कारण यह आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद की तथा आर्थिक और समाज परिषद की सदस्य संख्या भी बढ़ाई जाये। तदनुसार भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के गत सत्र में एक संकल्प पेश किया था जो बहुत अधिक मत से पारित हो गया था। इस संकल्प के अनुसार सुरक्षा परिषद की सदस्यता ११ से १५ हो गई है गौर आर्थिक तथा समाज परिषद की संख्या १८ से २७ हो गई है। जब दोनों परिषदों को बढ़ा दिया जायेग सेतब सुरक्षा परिषद् अफ्रीकी–एशियाई देशों के पांच अस्थाई पद बढ़ जायेंगे तथा आर्थिक तथा समाज परिषद में बारह पद बढ़ जायेंगे। संकल्प की क्रियान्विति के लिये चाटर में संशोधन करना होगा जो तभी लागू होगा जब संयुक्त राष्ट्र के दो तिहाई सदस्य जिनमें सुरक्षा परिषद के सभी स्थाई सदस्य भी होंगे, इसका अनुसमर्थन कर दें।

पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश

*१४३. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री जं० ब० सिंह० बिष्ट :

क्या **प्रधान मंत्री** १६ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तथा त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से अवैध रूप से आने वाले पाकिस्तानियों के प्रश्न पर विचार करने के लिये राजनयिक स्तर पर इस बीच प्रारम्भिक वार्ता हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यविहीन व्यक्ति

*१४४. **श्री धवन :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकारलाल बरवा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रधान मंत्री** ९ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लंका में भारतीय उद्भव के राज्यविहीन व्यक्तियों के मामले को निबटाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : ९ दिसम्बर, १९६३ से मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

'मिग' विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

*१४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कजरोलकर :
श्री कोला वेंकैया :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री प० ह० भील :
श्री कछवाय :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री बे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री नाथ पाई :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स्वैल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :

श्री बागड़ी :
श्री चुन्नीलाल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से हाल ही में प्राप्त किये गये ६ 'मिग'—२१ विमानों में से २ विमान चंडीगढ़ से 'फार्मेशन' में उड़ान करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गये ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई ; और

(ग) दुर्घटना का क्या कारण था ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) दोनों विमान एकदम बेकार हो गये हैं।

(ग) दुर्घटना की जांच के लिए जांच न्यायालय को आदेश दिए गए हैं। जांच न्यायालय की कार्यवाही मिल जाने पर दुर्घटना के कारणों का पता लगेगा।

Ghaziabad Villagers

*146. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(*a*) whether any final decision has been arrived at regarding payment of compensation for the acquired lands to the cultivators of neighbouring areas of Ghaziabad ;

(*b*) whether they have completely accepted the proposals made by the Prime Minister ; and

(*c*) if so, how and when they will get the compensation at the rates prevailing on the 9th February, 1962?

The Deputy Minister in the Ministry of external affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). As already stated in answer to Starred Question No. 579, dated December 16, 1963, the State Government had accepted most of the suggestions made by the Central Minister of Agriculture relating to payment of compensation for lands, wells, tube-wells and groves and grant of resettlement facilities. They had also agreed to base compensation at the market rates prevailing as on February 9, 1962. The proposal to pay solatium to the cultivators was under their consideration and they have not taken any final decision so far. The Prime Minister had not made any specific proposals about the matter. He had, however, repeatedly drawn the attention of the Chief Minister to give the cultivators fair compensation quickly.

(c) The awards in respect of a large portion of the land notified for acquisition have already been declared at 1960 rates and compensation has also been disbursed to a number of cultivators according to these awards. The State Government are examining as to how the difference between the rates of 1960 and those of 1962 is to be paid to the cultivators.

पूर्वी पाकिस्तान में दंगे

श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री नाथ पाई :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

*१४७. श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री ;
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री हेम बरुआ :
श्री कछवाय :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानन सन :
श्री कजरोलकर :
श्री हेम राज :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री च० का० भटटाचार्य :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स्वैल :
श्री बड़े :
श्री केप्पन :
श्री ह० च० सोय :

श्री पु० र० पटेल :
श्री गुलशन :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६३ तथा जनवरी, १९६४ के दौरान हुए उपद्रव में पूर्वी पाकिस्तान में जान तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई तथा वहां के अल्पसंख्यक समुदाय को कितना कष्ट उठाना पड़ा ; और

(ख) इस मामले के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उसने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). ११ फरवरी, १९६४ को गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा उस के बाद १२ तथा १३ फरवरी, १९६४, को हुई सभा में चर्चा की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

वायस आफ अमरीका ट्रांसमीटर करार

*१४८. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जेधे :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कोल्ला वेंकैय :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री १६ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में शक्तिशाली ट्रांसमीटर (१००० किलोवाट का) स्थापित करने के लिये वायस आफ अमरीका प्रस्ताव के संबंध में एक स्वीकार्य समझौता करने के बारे में और क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इस समय बात-चीत किस स्थिति में है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) स्थिति पहले जैसी **ही है** तथा और कोई प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

*१४६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जं० ब० सिंह० बिष्ट :
श्री ई० मधुसूदन राव : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल में ही पाकिस्तान ने विदेशों में, विशेषतया **अफ्रीकी**-एशियाई देशों में, भारत विरोधी प्रचार बढ़ा दिया है ; और

(ख) इस प्रचार का खंडन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हमारे दूतावास पाकिस्तानी प्रचार का पूरा ध्यान दे रहे हैं। कुछ मामलों में सरकारों का ध्यान मित्र देशों में भारत के विरुद्ध प्रचार के अनौचित्य की ओर भी दिलाया गया है । जिन मामलों में आवश्यक होता है उन में दूतावास पाकिस्तानी प्रचार का उत्तर भी देते हैं तथा बहुत से मामलों में संबंधित देशों के प्रचार साधनों में अपना उत्तर भी प्रकाशित कराते हैं। सभी प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं। जिससे दूतावासों को समाचारों तथा विचारों की ठीक-ठीक प्रति मिलती रहे जिससे पाकिस्तानी प्रचार द्वारा हुए बुरे प्रभाव को ठीक किया जा सके।

कई नये प्रचार पदों को बनाया गया है तथा दूतावासों द्वारा प्रपत्र तथा बार बार समाचारों का प्रसारण बढ़ाया जाता है । विदेशी भाषाओं विशेषत: फ्रांसीसी तथा अरबी में इन समाचारों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है । अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया के भारतीय दूतावासों के प्रमुखों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका में नये प्रचार केन्द्र खोले जा रहे हैं। ऐसे सम्मेलन जिन में पाकिस्तान भारत को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहा है ये भाग लेने वाले देशों के लाभ के लिये ठीक तथ्यों के प्रकाशन के लिये विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारतीय महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अफ्रीकी देशों के हाल के महीने में दौरे का भी पाकिस्तानी प्रचार का विरोध करने में तथा भारत के विचार व्यक्त करने में सहायता मिली है ।

आंध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार

२३५. { **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री ई० मधुसूदन राव : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को आन्ध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी

2202 (Ai) LS.—3.

थी ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कितने व्यक्ति हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चं० रा० पट्टाभिरामन): (क) ३८,८७५ शिक्षित व्यक्ति (मैट्रिकुलेट तथा अधिक) काम दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्टर में हैं :—

(ख)	अनुसूचित जातियों के	२५९८
	अनुसूचित आदिम जातियों के . . .	१९६१

पलना कोयला क्षेत्र, राजस्थान

२३६. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री १ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पलना कोयला क्षेत्र, राजस्थान के कल्याण केन्द्र के लिये भवन के निर्माण के लिये इस बीच उपयुक्त स्थान ले लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का मसले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रा० कि० मालवीय) (क) और (ख). २ एकड़ की जमीन इसके लिए छोड़ी गई है तथा इसके लेने के लिए और आगे कार्यवाही की जा रही है ।

पंजाब में तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति

२३७. **श्री बलजीत सिंह :** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६४ को पंजाब के काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने तकनीकी व्यक्ति रजिस्टर हैं ; और

(ख) अप्रैल, दिसम्बर, १९६३ में कितने तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) ७८४१ (दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक) ।

(ख) ४,७९५ ।

शिक्षित बेरोजगार

२३८. **श्री बलजीत सिंह :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६४ को देश में राज्यवार कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति थे; और

(ख) उन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की क्या संख्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख). ३१ दिसम्बर, १९६३ को देश में राज्यों के रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों

के अनुसार शिक्षित आवेदकों (मैट्रिकुलेट या उस से अधिक पढ़े हुए) की संख्या निम्न है :—

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	३१ दिसम्बर, १९६३ को चालू रजिस्टर पर दर्ज शिक्षित आवेदकों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियां (स्तम्भ २ में शामिल किया गया)	अनुसूचित आदिम-जातियां (स्तम्भ २ में शामिल किया गया)
आन्ध्र प्रदेश . .	३८,८७५	२,५९८	१९६
आसाम .	१०,८७६	४९६	५१८
बिहार .	४५,६७०	१,९८६	१,६१२
दिल्ली .	४३,५२१	२,३८२	२१
गुजरात .	२५,९०८	१,६१२	३८१
हिमाचल प्रदेश . .	१,६०६	१३३	१२
जम्मू तथा काश्मीर .	१,०४२	११	..
केरल . .	६८,१०७	१,९०१	९१
मध्य प्रदेश .	३५,४२०	१,३७६	४३३
मद्रास .	४२,८३६	२,१५४	६
महाराष्ट्र .	६५,८३८	६,३१४	३८४
मनीपुर .	१,४६१	१०	१३२
मैसूर . .	४६,५९४	२,७७०	१२
उड़ीसा	१२,८२८	१५०	२०४
पांडीचेरी	२७७	..	..
पंजाब	३१,५३६	२,६८७	७
राजस्थान	२५,४८२	९६७	३३०
त्रिपुरा	१,८०६	५४	६७
उत्तर प्रदेश	१,१७,५८६	१३,३५२	१
पश्चिमी बंगाल . .	१,२२,०९७	५,५७४	३११
अखिल भारतीय कुल : .	७,३९,०६६	४५,५२७	५,०१८

काठमांडू में गांधी स्कूल

- ह२२७

२३९. श्री राम सहाय यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने काठमांडू में गांधी आदर्श विद्यालय के संस्थापक को १.२५ लाख रु० की राशि का दान दिया ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां।

मैसूर में तकनीकी व्यक्ति

२४०. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ में मैसूर राज्य में विभिन्न रोज़गार दफ्तरों में कितने शिक्षित तकनीकी व्यक्तियों ने नाम दर्ज कराया ;

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६३ को मैसूर में विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितने दक्ष और अदक्ष व्यक्तियों ने नाम दर्ज कराया ; और

(ग) १९६२ और १९६३ में उन में से कितनों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्):

(क) दिसम्बर, १९६३ के अन्त में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्टरों में ९,४५४ तकनीकी व्यक्ति दर्ज थे।

(ख) और (ग).

आवेदकों के वर्ग	३१ दिसम्बर, १९६३ को दर्ज संख्या	रोज़गार दिलाये गये लोगों की संख्या	
		१९६२	१९६३
१. दस्तकार और उत्पादन परिष्करण कार्यकर्ता (दक्ष और अर्धदक्ष)	५,९७८	१,५७७	१,३०५
२. अदक्ष . . .	१५,३०६	३,८३२	४,७२१
३. अन्य व्यक्ति .	८८,४२०	१९,१६८	१६,०३६
कुल .	१,०९,७०४	२४,५७७	२२,०६२

संयुक्त राष्ट्र महासभा को भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

२४१. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के गत अधिवेशन में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल पर सरकार ने कुल कितना व्यय किया ; और

(ख) प्रत्येक सदस्य तथा मद पर कितना व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :

(क) २,९९,५००.०० रु० (लगभग)।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। **देखिये संख्या एल० टी० २३०१/६४**]

Safety and Sanitary Conditions in Factories

242. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Central Government propose to make the safety measures and sanitary conditions in factories more extensive and that it has been decided to amend the Factories Act, 1948 for the purpose; and

(b) if so, the salient features of the proposed scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) and (b). Provisions for health and safety of workers in factories are contained in Chapters III and IV of the Factories Act, 1948. It is proposed to amend the Act to provide for, *inter alia* :—

(i) enquiry by an Inspector into the more serious accidents with a view to ascertaining the causes, and taking suitable remedial and penal measures ;

(ii) the appointment of safety officers ;

(iii) powers for carrying out safety and occupational health surveys in factories : and

(iv) effective arrangements for treatment and disposal of wastes and effluents due to the manufacturing processes ; etc.

तिरुचिरापल्ली में शस्त्रों का कारखाना

२४३. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुचिरापल्ली में शस्त्रों का एक छोटा कारखाना स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने में कब उत्पादन आरम्भ होगा ; और

(ग) कारखाने की निर्धारित उत्पादन क्षमता क्या होगी।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) एक दूसरा छोटा शस्त्र कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है आशा है कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ?

हिन्द महासागर में ब्रिटेन की नौसेना टुकड़ी

श्री नाथ पाई :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री श्री० प्र० यादव :

२४४. { श्री बवन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार इन्डोनेशिया के सेनाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और सुरक्षा मंत्री जनरल अब्दुल हैरिस नसूशन द्वारा ३० दिसम्बर, १९६३ को जकारता में दिये गये इस वक्तव्य से अवगत है कि ब्रिटेन ने अपनी नौसेना टुकड़ी पहले से ही हिन्द महासागर में भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन की नौ सेना टुकड़ी कब से हिन्द महासागर में है; और

(ग) क्या ब्रिटेन के नौसेना अधिकारियों ने हिन्द महासागर में प्रवेश करने के लिये भारत सरकार से पूर्व अनुज्ञा ली थी ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जनरल अब्दुल हैरिस नसूशन के जिस वक्तव्य के बारे में प्रश्न किया गया है सरकार ने उसके बारे में समाचार पत्रों के समाचार देखे हैं परन्तु सरकार के पास कोई सरकारी जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) यह कोई नई परिस्थिति नहीं है और इसलिये प्रश्न नहीं उठता ।

नाइजेरिया के लिये भारतीय विशेषज्ञ

२४५. { श्री हेम बरुआ :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजेरिया के प्रधान मंत्री ने अपने हाल के दौरे में भारत सरकार से नाइजेरिया को भारतीय तकनीकी व्यक्ति और योजना विशेषज्ञ भेजने के बारे में बातचीत की ; और

(ख) नाइजेरिया के प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) नाइजेरिया के उत्तरी क्षेत्र के प्रधान मंत्री माननीय अलाहजी सर अहमदू बेल्लो ने दिसम्बर, १९६३ में भारत का दौरा किया । अपने दौरे के दौरान उन्होंने नाइजेरिया के उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के भारतीय तकनीकी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की संभावना के प्रश्न पर चर्चा की ।

(ख) अन्य विकासशील देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी नीति का अनुसरण करते हुए भारतीय सरकार नाइजेरिया के उत्तरी क्षेत्र की आवश्यकता पूरा करने के लिये सहर्ष भारतीय कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में भेजेगी ।

आकाशवाणी द्वारा संसद् की कार्यवाही सम्बन्धी प्रसारण

२४६. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित

प्रश्न संख्या ३०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद् की कार्यवाही से संबंधित प्रत्येक प्रसारण की एक लिपि, प्रसारण के शीघ्र ही पश्चात्, सभा पटल पर रखने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख) संसद् की कार्यवाही की समीक्षा से संबंधित आकाशवाणी पर प्रत्येक प्रसारण की लिपि की एक प्रति प्रसारण के पश्चात् संसद् पुस्तकालय को भेज दी जाया करेगी ।

Ordnance Factories

247. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yash Pal Singh :
Shri M. L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri P. C. Borooah :
Shri Maheshwar Naik :
Shri Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hem Raj :
Shri D. C. Sharma :
Shri A. V. Raghavan :
Shri Kappen :
Shri Mohan Swarup :
Shri Koya :
Shri N. Rampure :

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(*a*) the up-to-date progress made in the schemes for extending the existing ordnance factories as also for establishing some new factories;

(*b*) whether any foreign assistance is also likely to be available to this end, and if so, by when ; and

(*c*) whether some experienced persons helpful in the manufacture of latest types of modern armaments are also likely to arrive here from abroad ; and if so, when they would be able to start their work ?

The Minister of defence production in the Ministry of Defence (Shri Raghu Ramaiah) : (*a*) Schemes for modernising machine shops, tool rooms and material handling facilities in the existing Ordnance Factories have been sanctioned and are under implementation. A complex of six new factories is also under contemplation. It will not be in the public interest to give a detailed account of the progress made in the establishment of the new factories as well as in modernising the existing Ordnance Factories.

(*b*) US assistance has been secured for the bulk of the plant and machinery in respect of one of the new factories and UK assistance has been secured for meeting part of the expenditure in a second factory. Foreign aid for procurement of plant and machinery is proposed to be taken for the remaining factories and for the schemes of modernisation in the existing factories as may be necessary and available.

(*c*) There is at present no proposal to employ foreign specialists.

मध्य वर्गीय लोग

२४८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रधान मंत्री १६ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८० तथा उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शहरी मध्यवर्ग के कर्मचारियों के परिवारों की रहने की दशाओं से संबंधित सारणीकरण पूरा हो गया है और प्रतिवेदन तैयार कर लिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, वदैशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी, नहीं । सारणीकरण का कार्य काफी किया जा चुका है, परन्तु अभी भी कुछ शेष रहता है ।

अमरीका से हथियार

२४९. **श्री विशन चन्द्र सेठ :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री चवन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो और सेना डिवीजनों को अमरीका सरकार से हथियार संभरण के संबंध में क्या कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो हथियार कब आयेंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीकी सरकार ने भारतीय वायु सेना को शक्तिशाली बनाने में सहायता देने का आ अश्वासन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) (क) मामले पर अभी भी चर्चा हो रही है ।

(ख) उपरकणों के संभरण के बारे में सिद्धान्त रूप से निर्णय होने के पश्चात् ही देने की तिथि निश्चित की जा सकती है ।

(ग) और (घ) जी, हां । सहायता अमरीका के बने विमानों, हवाई अड्डे पर भूमि में लगे हुए उपकरण, संचार और रडार उपकरण के लिये पुर्जों के संभरण के रूप में होगी ।

आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकार

२५०. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकारों की सेवा की शर्तों संबंधी विभागीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है और उस पर निर्णय कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) विभागीय समिति का प्रतिवेदन अभी भी विचाराधीन है । -संसद् कार्य

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम के साथ नेफा का एकीकरण

२५१. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में नेफा का आसाम के आस पास के मैदानों से एकीकरण करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जिला अधिकारियों की स्थानीय बैठकों के अतिरिक्त नेफा राजनैतिक अधिकारियों और आसाम के डिप्टी कमिशनरों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है । नेफा और आसाम दोनों के लिये एक संयुक्त निदेशक, भूमिसंरक्षण की नियुक्ति की गई है । आसाम लोक सेवा आयोग का एक सदस्य स्थानीय नेफा संवरण बोर्डों में बैठता है । नेफा के पांच जिलों में से तीन का पूर्ण भार इस समय आसाम से भरती किये गये आई० एफ० ए० एस० प्रवर्ग के वरिष्ठ वेतन मान अधिकारियों के हाथ में है । बाद में अधिकारियों की अदलाबदली में सुविधा के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम और कनिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारियों के लिये भरती के नियम ठीक वैसे ही हैं जैसे कि आसाम में जो कि लोकहित में है ।

१९६३ में अनेक सांस्कृतिक शिष्ट-मंडलों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और चिकित्सा छात्रों के दलों ने नेफा का दौरा किया । एक बड़ी संख्या में नेफा के विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिये आसाम में शिक्षा पा रहे हैं । नेफा के तिराप सीमान्त सत्ताधिकारियों के परम्परागत दौरे पुनः प्रारम्भ किये गये हैं और उनमें सफलता मिली है । आसाम सरकार नेफा क मैदानी स्थानों में आने वाले भ्रमणार्थियों के ठहरने के लिये कुछ कुटियों का निर्माण कर रही है और स्थानीय रूढिगत व्यापार के संवर्द्धन के लिये उपाय किये जा रहे हैं । आसाम विपणन निगम नेफा कुटीर उद्योगों के उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित करने तथा उनकी बिक्री के लिये कदम उठा रहा है । वे अन्तर्प्रदेश में कुछ कच्चे सामान के संभरण के नेफा लिये व्यवस्था कर रहा है । आसाम और नेफा के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में इन दोनों क्षेत्रों की परस्पर जानकारी दी गई है ।

वृद्ध और अपंग व्यक्तियों को सहायता

२५२. श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से वृद्ध और अपंग व्यक्तियों और आश्रित महिलाओ और बालकों को सहायता देने के लिये अग्रिम आधार पर कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जी हां ।

(ख) मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, केरल महाराष्ट्र और पंजाब की सरकारों और त्रिपुरा और गोआ, दमन और दीव के प्रशासनों ने सूचना दी है कि मामला विचाराधीन है । अन्य राज्यों और संघ क्षेत्रों से उत्तर की प्रतीक्षा है ।

International Film Festival

253. **Shri Vishram Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Third International Film Festival is going to be held in New Delhi in November, 1964 ; and

(b) if so, the names of the countries who will participate in that festival ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) It is not possible to indicate at present the names of the countries which will participate in the III International Film Festival of India.

दक्षिण भारत में आणविक विद्युत केन्द्र

२५४. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री बालकृष्णन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में एक आणविक विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिये कोई उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). यह निर्णय किया गया है कि तीसरा आणविक विद्युत केन्द्र मद्रास राज्य में तट पर कलपक्कम में लगाया जायेगा, परन्तु इस केन्द्र का कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया गया हैं ।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि और मंहगाई भत्ता

२५५. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्य निधि और मंहगाई भत्ते के अंशदान की बढ़ी हुई दर को अधिक उद्योगों पर लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन उद्योगों पर विचार किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत भविष्य निधि के अंशदान की बढ़ी हुई दर को लागू करने का प्रश्न निम्न उद्योगों/संस्थापना के वर्ग के संबंध में विचाराधीन है :

१. चाय बागान (आसाम राज्य के चाय बागान को छोड़ कर)।
२. काफी के बागान ।
३. रबड़ के बागान ।
४. इलायची के बागान ।
५. काली मिर्च के बागान ।
६. कच्चे लोहे की खानें ।
७. मैंगनीज की खानें ।
८. चूने की खानें ।
९. सोने की खानें ।
१०. औद्योगिक और 'पावर एलकोहल' उद्योग ।
११. एसबेसटॉस सीमेंट चादरों का उद्योग ।
१२. काफी सुखाने के संस्थापन ।

परन्तु विभिन्न उद्योगों में सामान्य रूप से मंहगाई भत्ता बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

केन्द्रीय सूचना सेवा

२५६. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या क्या है और इसकी वर्तमान श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) क्या अभी भी कोई रिक्त स्थान है; और

(ग) क्या सेवा में निम्नतर श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिये सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है ?

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा की स्वीकृत संख्या श्रेणीवार निम्न प्रकार है :

श्रेणी और वेतन मान	पदों की संख्या
वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी :	
१,८००—१००—२,००० रु०	१
१,६००—१००—१,८०० रु०	२
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी :	
१,३००—६०—१,६०० रु०	७
१,१००—५०—१,४०० रु०	१४
श्रेणी १ (७००—४०—१,१००—५०।२—१२५० रु०)	६४
श्रेणी २ (४००—४००—४५०—३०—६००—३५—६७०—ई० बी०—३५—९५० रु०)	८९
श्रेणी ३ (३५०—२५—५००—३०—५९०—ई० बी० ३०—८०० रु०)	१४८
श्रेणी ४ (२७०—१०—२९०—१५—४१०—ई० बी० १५—४८५)	३४९
कुल	७०५

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । निम्नतर श्रेणियों से उच्चतर श्रेणियों में पदोन्नतियां समय समय पर संशोधित किये गये सी० आई० एस० नियमों, १६५६ के नियम, ६ के अनुसार की गई हैं । कुछ मामलों में पदों की तदर्थ नियुक्तियां बिलकुल अस्थायी व्यवस्था के रूप में की जाती हैं जो कि बाद में नियमों के अनुसार भर ली जाती हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग

२५७. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेखा परीक्षकों ने मंत्रालय को ५ लाख रुपये की हानि के बारे में बताया है जो कि प्रकाशन विभाग की बहुत सारी मूल्य वाली पुस्तकों से हुई है जिनका कि कोई हिसाब नहीं रखा गया है ;

(ख) क्या यह मामला जांच करने के लिये विशेष पुलिस संस्थान को सौंप दिया गया है ; और

(ग) क्या एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिसमें १६५६–६० से लेकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हुई ऐसी हानियों का ब्यौरा दिया जायेगा ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ग). जी, हां । लेखा परीक्षकों ने प्रकाशन विभाग के स्टाक्स में कुछ घटोतरियां/बढ़ोतरियां मंत्रालय को बताई हैं । सम्भावना यह है कि हानि ५ लाख रुपये से तो बहुत हो कम की होगी । तथापि, स्टाक की प्रत्यक्ष जांच की जा रही है और जांच के पूरा होने के पश्चात् ही वास्तविक स्थिति का पता लगेगा । इस समय हानि के वर्षवार ब्यौरे बता सकना सम्भव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

उद्योग में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें

२५८. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औद्योगिक क्षेत्र में इस समय कितनी संयुक्त प्रबन्ध परिषदें कार्य कर रही हैं ; और

(ख) इन परिषदों की शक्तियां तथा कार्यक्षेत्र क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रा० कि मालवीय) : (क) ८० ।

(ख) संयुक्त प्रबन्ध परिषदों से ऐसे मामलों पर परामर्श लिया जाता है जैसे कि स्थायी आदेश तथा उनके संशोधन, कल्याण कार्यों और सुरक्षा उपायों का प्रबन्ध । उपक्रम की आर्थिक तथा वित्त संबंधी स्थिति, विपणन और अन्य सम्बद्ध कार्यों से संबंधित मामलों पर उनकी जानकारी दी जाती है । प्रत्येक संयुक्त प्रबन्ध परिषद् की शक्तियां तथा उनका कार्यक्षेत्र संबंधित प्रबन्धकर्ताओं तथा

संघ के बीच हुए करार में दिया जाता है, जो कि सामान्यतया प्रारूप आदर्श करार के अनुरूप होता है जिसकी कि एक प्रति साथ संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० २३०२/६४]

सैनिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण

२५६. { श्री रा० गि० दुबे :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना में भावी अधिकारियों और जवानों की मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक परीक्षा ली जाती है जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाये कि यंत्रीकृत युद्धकला के लिए आवश्यक शारीरिक तथा मानसिक कौशल्य के उच्चतम स्तरों पर वे पूरे उतरें ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परीक्षाओं का क्या परिणाम निकला है ? और

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी, हां; सिवाय इसके कि मनोवैज्ञानिक परीक्षायें केवल कमीशन वाले पदों के अभ्यर्थियों की ही ली जाती हैं।

(ख) कुल मिलाकर परिणाम संतोषजनक निकले हैं। प्रारम्भिक चयन के पश्चात् जिन रंगरूटों की डाक्टरी परीक्षा ली गई थी उनमें से अन्दाजन आधे डाक्टरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इमरजेंसी कमीशन के लिये आये जिन अभ्यर्थियों ने सर्विसेज सलेक्शन बोर्ड्स के सामने परीक्षायें दी थीं (जिनमें मनोवैज्ञानिक परीक्षायें भी सम्मिलित हैं) उनमें से लगभग २१.६ प्रतिशत सफल हुए थे और इन सफल हुए अभ्यर्थियों में से ८६ प्रतिशत डाक्टरी जांच में पास हुए थे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण

२६०. { श्री भो० प्र० यादव :
श्री यवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समर्थांग सरकारी कर्मचारियों को सैनिक प्रशिक्षण देने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) केवल असैनिक सरकारी कर्मचारियों को ही सैनिक प्रशिक्षण देने की कोई योजना नही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रादेशिक सेना असैनिक सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को कुछ शर्तों पर उनके नागरिक जीवन में अव्यवस्था लाये बगैर ही सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर देती है। इसी प्रकार सीमावर्ती राज्यों के सरकारी कर्मचारी लोक सहायक सेना योजना का लाभ उठा सकते हैं जिसके अधीन १५ दिवसीय शिविरों में असैनिक जनता को प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण

दिया जाता है। "असैनिक राइफल प्रशिक्षण केन्द्रों" के नाम से भी एक योजना है जो गृह-कार्य मंत्रालय के निदेश में चलाई जाती है तथा जिसका, अन्य व्यक्तियों के साथ साथ, सरकारी कर्मचारी भी लाभ उठा सकते हैं।

ये जो योजनायें चल रही हैं इनको देखते हुए असैनिक सरकारी कर्मचारियों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए पृथक से एक योजना आरम्भ करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

ब्रिटेन के जहाज की भारत यात्रा

२६१. **श्री धवन :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन का एक अत्यन्त आधुनिक लड़ाकू जहाज २१ दिसम्बर, १९६३ को भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य था और उसकी इस यात्रा से भारत को क्या सहायता मिली ;

(ग) क्या भारत के ब्रिटेन से इस प्रकार के जहाज खरीदने की आशा है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। ब्रिटिश नौसैना के नवीनतम सामान्य प्रयोजन रणपोतों में से एक, एच० एम० एस० नुबियन, २१ से २७ दिसम्बर, १९६३ तक बम्बई आकर ठहरा था तथा २९ दिसम्बर, १९६३ से २ जनवरी, १९६४ तक कोचीन में जाकर।

(ख) इन यात्राओं का प्रयोजन मुख्यतया सैन्यसंचालन संबंधी आवश्यकताओं और सद्भावना से संबंधित था। भारतीय नौसैना के कर्मचारियों को नौसैनिक उपकरण में नवीनतम विकासों को देखने का अवसर मिला।

(ग) ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सैनिक स्कूल

२६२. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हेमराज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने सैनिक स्कूल चल रहे हैं ;

(ख) किन राज्यों में अभी सैनिक स्कूल खोले जाने हैं ; और

(ग) ऐसे राज्यों द्वारा सैनिक स्कूल न खोलने के क्या कारण बताये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) तेरह ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश, आसाम, जम्मू तथा काश्मीर और नागालैण्ड ।

उत्तर प्रदेश और आसाम राज्य इन स्कूलों को स्थापित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गये हैं। इन दो स्कूलों में सैनिक स्कूलों के स्थान चुने जा रहे हैं। नागालैण्ड और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों ने सैनिक स्कूलों में जो इन राज्यों के बाहर स्थित हैं अपने यहां बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां आरम्भ की हैं।

आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

२६३. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अस्पताल और औषधालयों को बनाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस संबंध में अब तक कुल कितना रुपया व्यय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे०रा० पट्टाभिरामन): (क) (१) अब तक निम्नलिखित वार्डस / औषधालय बना दिये गये हैं और वे चल रहे हैं :—

(१) राजयक्ष्मा अस्पताल, इर्रम्मुना में २४ पलंगों वाला क० रा० बी० यो० का वार्ड ।

(२) वाई० ई० एम० अस्पताल, सिकन्दराबाद में ३२ पलंगों वाला क० रा० बी० यो० वार्ड ।

(३) चार डाक्टरों वाला राज्य बीमा योजना औषधालय, कवाडीगुडा, हैदराबाद ।

(२) निम्नलिखित अस्पताल / औषधालयों के भवनों का निर्माण हो रहा है :—

(१) १५० पलंगों वाला क० रा० बी० यो० अस्पताल, हैदराबाद ।

(२) ५० पलंगों वाला क० रा० बी० यो० अस्पताल, सीरपुर—कागज़नगौर ।

(३) चार डाक्टरों वाला राज्य बीमा योजना औषधालय, नेल्लिमरला ।

(४) चार डाक्टरों वाला राज्य बीमा योजना औषधालय, चितिवालसा ।

(५) चार डाक्टरों वाले राज्य बीमा योजना के दो औषधालय, सीरपुर—कागज़नगर ।

(३) निम्नलिखित अस्पतालों / औषधालयों की योजनायें तथा प्राक्कलन मंजूर कर दिये गये हैं परन्तु निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है :—

(१) ११० पलंगों वाला क० रा० बी० यो० अस्पताल, विशाखापटनम ।

(२) चार-डाक्टरों वाला क० रा० बी० यो० औषधालय, वारंगल ।

(ख) अभी तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अस्पतालों/औषधालयों के निर्माण के लिये राज्य सरकार को ४८,८८,५६६ रुपये ३५ नये पैसे दिये हैं।

भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोत

२६४. श्री प० कुन्हन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री दिनांक १८ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लिये युद्धपोतों का स्वदेश में निर्माण करने के संबंध में अब तक कोई निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया : (क) और (ख) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

सामूहिक संचार[1]

२६५. { श्री प० कुन्हन : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दिनांक १८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक संचार का उच्च अध्ययन करने के हेतु एक केन्द्र स्थापित करने के संबंध में फोर्ड फाउण्डेशन के विशेषज्ञों के दल ने जो प्रस्ताव दिया था क्या उसके संबंध में अब तक कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है ।

ASIAN BROADCASTERS' CONFERENCE

*266 **Shri Sidheswar Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 14 on the 18th November, 1963 and state :

(*a*) whether Government have since considered the proposals of the Asian Broadcasters' Conference ;

(*b*) if so, the decisions taken thereon ; and

(*c*) the steps taken or proposd to be taken to implement them ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satyanarayan Sinh): (a) The proposal regarding the All India Radio becoming a member of the Asian Broadcasting Union is still under consideration of the Government of India.

(*b*) & (*c*) Do not arise.

[1]Mass Communication

यात्रा करने वाले सैनिकों के लिए सुविधायें

२६७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हावड़ा होकर जाने वाले सैनिक के लिए विश्राम, नहाने धोने तथा कैंटीन सेवाओं से संबंधित पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे कर्मचारियों के सहयोग से शीघ्र ही आवश्यक स्थान और सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) हावड़ा रेलवे स्टेशन होकर जाने वाले सैनिकों के लिए वहां पर विश्राम, नहाने-धोने तथा कैंटीन सेवाओं से संबंधित कुछ सुविधायें तो इस समय उपलब्ध हैं। उनका पुनर्विलोकन किया जा रहा है और रेलवे अधिकारी जहां तक व्यवहार्य हो सके वहां तक अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गये हैं।

चण्डीगढ़ में क्षेत्र प्रचार अधिकारियों का शिविर

२६८. **श्री हेमराज :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी प्रदेश के क्षेत्र प्रचार अधिकारियों का गत दिसम्बर में चण्डीगढ़ में एक शिविर लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वह कितने दिन रहा, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे और उस शिविर में अधिकारियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ग) किन किन राज्यों ने इसमें भाग लिया था ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) शिविर सात दिन तक लगा था। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र प्रचार अधिकारियों को "सेवा में प्रशिक्षण" देना था और अपने सामान्य कार्य को करने में उनके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनके संबंध में उनके ज्ञान और विचारधारा को तरोताजा करना था।

(ग) पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र।

'पवित्र बाल' के खोने के सम्बन्ध में आकाशवाणी के प्रसारण

२६९. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 'पवित्र बाल' के मिल जाने के सम्बन्ध में रेडियो श्रीनगर से की गई सरकारी घोषणा के बाद भी आकाशवाणी, नई दिल्ली के समाचारों में उसकी तलाश और खेद की बात का समाचार दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी भूल के कारणों का विश्लेषण करने और इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

2202(ai LS—5

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) पवित्र बाल के मिल जाने की सूचना आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग को उस समय प्राप्त हुई थी जब कि दिल्ली से काश्मीरी भाषा में सायंकालीन समाचार प्रसारित किये जा रहे थे और तुरन्त ही उस समाचार को समाचारों में सम्मिलित कर लिया गया था। क्योंकि समाचार उस समय प्राप्त हुआ था जब कि समाचार देने प्रारम्भ किये जा चुके थे इसलिये समाचारों के प्रथम भाग में स्वभावतः ही उस समय वही सूचना दी गई थी जो कि उस समय उपलब्ध थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

WOUNDED SOLDIERS

270. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the soldiers, who lose their eyes in war, are sent to Blind Training Centre, Dehra Dun;

(b) the names of the places other than Dehra Dun where they can be sent; and

(c) the nature of the assistance which Government give to them and their families ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (*a*) Blinded ex-servicemen are eligible for admission on a priority basis into the Training Centre for the Adult Blind at Dehra Dun which is administered by the Ministry of Education.

(*b*) Government are not aware of any other such training centre.

(*c*) The following assistance is given :—

(i) Free board, lodging and tuition, pocket money at the rate of Rs. 6·00 p.m., clothes and medical aid during the period of training which ususlly is about 2 years.

(*ii*) On completion of training aftercare and resettlement grants upto Rs. 2,500·00 from St. Dunstan's (India) Fund which is a non-public fund.

(*iii*) A special pension of Rs. 10 p.m.from the ISS&A Board Fund which is also a non-public fund. This special pension is in addition to pension which the blinded ex-servicemen may get from the Government.

ATOMIC SCIENCE

271. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(*a*) whether it is fact that 14 Indian students have been sent to France for studies in atomic science ;

(*b*) if so, the qualifications on the basis of which they have been sent ; and

(*c*) the number of Scheduled Caste students among them ?

The Prime Minister Minister of External Affairs & Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) . (*a*) So far 20 Indian scientists/

engineers (not students) of the Department have been sent to France for advanced training on scholarships under the Indo-French Technical Co-operation Agreement and those offered directly to the Department of Atomic Energy by the Government of France.

(*b*) The selected officers had post-graduate qualifications and were sent for further advanced specialised training as required for the work of the Department.

(*c*) None of those sent to France so far belong to a Scheduled Caste.

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विशेष अधिकारी

२७२. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को श्रमिकों सम्बन्धी मामलों पर सलाह देने के लिए कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम क्या है ; और

(ग) उसे क्या कर्त्तव्य सौंपे गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जी हां ।

(ख) श्री आर० आई० मेहता ।

(ग) सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों में श्रमिकों सम्बन्धी विधियों की क्रियान्विति को देखना तथा प्रबन्धकों और मजदूरों को श्रमिकों सम्बन्धी मामलों पर सलाह देना ।

मनाली उपशी सड़क

२७३. { **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनाली उपसी सड़क को बनाने का प्रस्ताव है जो कि कुल्लू को पूर्वी लद्दाख से मिलायेगी ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्माण कार्य १९६४ की गर्मियों में प्रारम्भ होगा ।

(ग) मोटे हिसाब के आधार पर परियोजना की अनुमानित लागत २० करोड़ रुपये होगी।

महाराष्ट्र में आयुध कारखाना

२७४. { श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री प० ह० भील :
श्री सोलंकी :
श्री हिम्मतसिंह जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कोया :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में अमरीकी सहायता से एक आयुध कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मशीनें अमरीका से यहां पर कब पहुंच जायेंगी ; और

(ग) कारखाने में कब उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) महाराष्ट्र में एक आयुध कारखाना स्थापित किया जा रहा है। सहायता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में अमरीका संयंत्र और मशीनों के एक बड़े हिस्से के लिये पूंजी लगा रहा है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित मशीनों के जून, १९६४ के अन्त से पहले ही यहां पहुंच जाने की आशा है।

(ग) यह आशा की जाती है कि प्रयोगात्मक उत्पादन वर्ष १९६४ की समाप्ति से पहले ही प्रारम्भ हो जायेगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन १९६५ के प्रारम्भ में।

सीमा सड़क संगठन के अधिकारी की मृत्यु

२७५. { श्री हेम बरुआ :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री स्वैल :
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही सीमा सड़क संगठन के कैम्प कमांडर, मेजर डाहवाल को मिजो पहाड़ियों में जभबक में भीड़ ने मार डाला था ; और

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई थी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) मेजर डाहबाल तथा दो अन्य व्यक्ति जिन परिस्थितियों में मारे गये तथा कुछ व्यक्ति घायल हो गये उसकी न्यायिक जांच की जा रही है।

नागालैंड में नागा विद्रोहियों की कार्यवाही

२७६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री स्वैल :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री जो० ना० हजारिका :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) नागालैंड में हुए अभिचुनावों में नागाविद्रोहियों द्वारा तोड़फोड़ तथा शांति भंग करने की कितनी घटनायें की गईं ;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं का विवरण क्या है ; और

(ग) कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा इन घटनाओं में विद्रोहियों द्वारा कितनी सम्पत्ति की क्षति की गई ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ३३ घटनायें हुई थीं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—२३०३/६४]**

(ग) (१) हत—७ सुरक्षा सेना सैनिक
आहत—१ सुरक्षा सेना सैनिक
१ असैनिक

(२) सम्पत्ति नष्ट/समाप्त—१ राइफल .३०३ तथा ५० कारतूस मेलूरी गांव के कुछ गांवों में झौपड़ियां जला दी गईं। ततचायी में छोड़ा गया शिविर जला दिया गया।

Army Cadet College, Nowgong

277. **Shri R. S. Tiwary :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Army Cadet College is being shifted from Nowgong to Poona ;

(b) if so, the reasons for shifting the same from Nowgong ; and

(c) how the building of the College at Nowgong is proposed to be utilised?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) Yes, Sir. It has been decided to shift the Army Cadet College from Nowgong to Poona.

(b) It has been decided to increase the strength of Cadets at Army Cadet College to 650 against which Nowgong has accommodation only for 230. As the Officers Training School, Poona is being closed down and there is enough accommodation to accommodate more than 650 Cadets there, it has been decided to shift Army Cadet College to Poona.

(c) This matter is under consideration.

इंजीनियरिंग स्नातकों में बेरोजगारी

२७८. श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग स्नातकों में कितनी बेरोजगारी है; और

(ख) क्या ऐसा उम्मीदवारों की अनुपलब्धता अथवा उनको अवसर न मिलने के कारण है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) और (ख). पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है । परन्तु दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक काम दिलाऊ दफ्तरों में काम के इच्छुक इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या १७५८ थी। ये बेरोजगार प्रतियोगिताओं के कारण हैं तथा रोजगार के कम अवसर मिलने के कारण नहीं है ।

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

२७९. श्री हेम राज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि का विस्तार करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जी नहीं। तीन राज्य सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड

२८०. श्री हेम राज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना के बढ़ जाने के कारण तथा बोर्ड पर काम का दबाव बढ़ जाने पर क्या सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड के संगठन को शक्तिशाली बनाने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : सैनिक नाविक तथा वैमानिक, संगठन को बढ़ाने तथा शक्तिशाली बनाने के निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(१) जहां पर आवश्यक था वहां पर ५ नये सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड बना दिए गए हैं।

(२) ३ द्वितीय श्रेणी के जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों को प्रथम श्रेणी का बना दिया गया है।

(३) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के काम करने के लिये प्रयोगात्मक आधार पर ५ राज्यों में कल्याण कर्मचारियों के ६१ पदों को स्वीकार कर लिया गया है।

(४) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि अंशकालिक अथवा पदेन सचिवों के स्थान पर राज्य बोर्डों के पूरे समय के अधिकारियों को सचिव नियुक्त करे।

(५) आठ राज्यों तथा तीन संघ राज्य क्षेत्रों में सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड संगठन को स्थायी बना दिया गया है तथा शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ समय में ऐसा किए जाने की आशा है।

(६) कई जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों में जिनमें ऐसा करना उचित था अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति दे दी गई है।

मद्रास का "इण्डियन एक्सप्रेस"

२८१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इण्डियन एक्सप्रेस' का मद्रास संस्करण पुनः प्रकाशित होने लगा है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अपने अन्तिम सम्मेलन में इसके बन्द करने तथा पुनः प्रकाशन के मामले में पूरी जांच करने के लिए कहा गया है; और

(ग) इसको अखबारी कागज कैसे मिला ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) मद्रास के संस्करण के लिए 'इंडियन एक्सप्रेस' को अखबारी कागज का अलग से कोई कोटा नहीं दिया गया है। परन्तु समाचारपत्र को अपने चित्तूर संस्करण का कुछ कोटा मद्रास संस्करण को देने की अनुमति दे दी गई है।

MILITARY AREA IN SAUGOR DISTRICT

282. **Shri Bade :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government propose to declare 21 villages near Bina in district Saugor in Madhya Pradesh as military area ;

(b) if so whether Government have received any representation from the people of that area that their land should not be acquired for this purpose ; and

(c) whether Madhya Pradesh Government have recommended any rate of compensation to be paid to the affected villagers ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Raghuramaiah): (a) A proposal to establish a defence establishment near Bina for the proof of weapons and ammunition is under consideration. The acquisition of the area has not yet been progressed, but the proposal involves lands belonging to 21 villages, some affected partly.

(b) Yes, Sir. The representations are under consideration in consultation with the Government of Madhya Pradesh.

(c) Compensation will be paid to those affected according to the provisions of the Land Acquisition Act.

कोचीन के निकट विमान दुर्घटना

२८३. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ दिसम्बर, १९६३ को कोचीन के निकट हुई विमान दुर्घटना में नौ सेना के "एयर स्क्वैड्रन" का एक कर्मचारी मर गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना कैसे हुई ;

(ग) क्या सरकार ने जांच के लिये कोई समिति गठित की है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) जांच बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी है कि दुर्घटना चालक की निर्णय सम्बन्धी भूल किये जाने के कारण हुई। विमान कुछ ही सैकिंड में नियंत्रण से बाहर हो गया और विमान के पानी को छूने के बाद चालक बाहर नहीं निकल सका।

(ग) जी, हां।

(घ) जांच बोर्ड की उपपत्तियां सरकार के विचाराधीन हैं।

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा

२८४. **श्री स्वैल :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के लुबाचेरा क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण पूरा हो गया है :

(ख) क्या पाकिस्तान के साथ कोई समझौता हो गया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) यह तय हुआ है कि जब तक भूमि पर रेखांकित अन्तर्राष्ट्रीय सीमा स्वीकार न की जाये तब तक पूर्वी पाकिस्तान की राइफल सेना (पाकिस्तान) के सैनिक न तो संयुक्त सर्वेक्षण सीमांकन रेखा के १५० गज के अन्दर रहेंगे तथा न ही कोई प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य इस क्षेत्र के अन्दर किया जायेगा तथा सीमा सुरक्षा बल (भारत) क्षेत्र के चाय बगीचे की कटी हुई झाड़ियों की पंक्ति से १५० गज दूर रहेगा ।

ACCIDENTS IN COAL MINES

285. **Shri Bade :** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(*a*) the number of major and minor accidents which occurred in coal mines of Madhya Pradesh during 1963 ; and

(*b*) the loss of life and property caused by such accidents?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya): (a) and (b). 38 fatal accidents involving 47 deaths and 542 serious accidents occurred. The number of minor accidents is not available. No loss of property has been reported.

परभणी में ट्रांसमिटर

२८६. **श्री लोनीकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परभणी में ट्रांसमिटर लगाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने नक्शे तथा रूपांकन स्वीकृत कर दिये हैं ?

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): (क) और (ख). परभणी में ट्रांसमिटर की इमारत के निर्माण सम्बन्धी नक्शे जो कि राज्य सरकार के वास्तुकार द्वारा तैयार किये गये थे, स्वीकार किये जा चुके हैं । इमारत के निर्माण सम्बन्धी अन्तिम प्राक्कलन राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । पारेषण उपकरण उपलब्ध है तथा मस्तूल रेडिएटर के लिये मांग पत्र भेज दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा ट्रांसमिटर की इमारत तैयार किये जाने के बाद ४ महीने के अन्दर परियोजना पूरी हो जायेगी ।

केरल के हज यात्री

२८७. **श्री कोया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रा के दौरान मक्का में केवल दो मुअालिमों का एकाधिकार होने के कारण केरल के हाजियों को हुई कठिनाइयों की ओर सऊदी अरब की सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सऊदी अरब की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). जेद्दाह स्थित अपने राजदूतावास के द्वारा सऊदी अरब की सरकार से प्रार्थना की गई है, कि वह केरल के हाजियों की देखभाल करने के लिये और अधिक मुअालिम नियुक्त करे । वहां की सरकार का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

जापान के विमान दल की यात्रा

२८८. श्री दे० द० पुरी :
श्री रा० बरुग्रा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री हेम बरुग्रा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान के नौ सदस्यीय विमान दल ने हाल में जो भारत की यात्रा की थी क्या उसके लिये भारत सरकार ने निमंत्रण दिया था ;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रतिरक्षा सम्बंधी आवश्यकताओं के लिये जापान से विमान खरीदने का है ; और

(ग) क्या भारत में विमानों के निर्माण के लिये जापान का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ग) इस समय नहीं ।

कार्मिक संघों को मान्यता देना

२८९. **श्री शशिरंजन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कार्मिक संघों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकार ने उनकी सदस्यता का सत्यापन करने के बाद मान्यता प्रदान की है ; और

(ख) क्या स्वतंत्र कार्मिक संघों के संघ ने मान्यता प्राप्त करने के लिये यह प्रार्थना की है कि उनकी सदस्यता का सत्यापन किया जाय ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) बातचीत तथा परामर्श के प्रयोजनार्थ कार्मिक संघों को सरकार द्वारा नहीं अपितु सम्बन्धित नियोजकों द्वारा मान्यता दी जाती है । तथापि, सरकार ने निम्नलिखित चार अखिल भारतीय कार्मिक संघ संगठनों को इनकी सत्यापित सदस्यता के आधार पर विभिन्न त्रिपक्षीय परिषदों, बोर्डों, समितियों तथा राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधान देने के लिये मान्यता प्रदान की हुई है :—

१. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

२. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

३. हिन्द मज़दूर सभा ।

४. यूनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

(ख) जी, हां, अक्टूबर, १९६२ में ।

दक्षिणी अफ्रीका के साथ व्यापार सम्बन्ध

२९०. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **प्रधान मंत्री** ९ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के साथ व्यापार सम्बन्ध तोड़ दिये हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से प्राप्त मंत्रणा के अनुसार अब तक निम्न देशों ने ६ नवम्बर, १९६२ को स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र के संकल्प संख्या १७६१ (सत्रह) के अनुसरण में, दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य के साथ व्यापार संबंध तोड़ दिये हैं :—

(१) अफगानिस्तान (२) अल्जीरिया (३) बोलीविया (४) बुरुंडी (५) बर्मा (६) कम्बोडिया (७) कैमरून (८) चड (९) कोस्टारिका (१०) चैकोस्लोवाकिया (११) दहोमी (१२) इथोपिया (१३) घाना (१४) गिनी (१५) हंगरी (१६) हेटी (१७) भारत (१८) इन्दोनेशिया (१९) आइवरी कोस्ट (२०) जमेका (२१) केन्या (२२) कुवैत (२३) लीबिया (२४) मालागासी गणराज्य (२५) मलेशिया (२६) माली (२७) नेपाल (२८) ——————— (२९) नाइजीरिया (३०) पाकिस्तान (३१) फिलीपाइन्स (३२) रूमानिया (३३) सियरा लियोने (३४) सोमाली (३५) सूडान (३६) सीरिया (३७) टंगानीका (३८) उगांडा (३९) संयुक्त अरब गणराज्य (४०) अपर वोल्टा (४१) युगोस्लाविया (४२) जंजीबार ।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट से दिनांक १६ फरवरी, १९६४ का निम्नलिखित बेतार का सन्देश प्राप्त हुआ है जिस की सूचना मुझे सभा को देनी है :—

> "लोक-सभा के सदस्य, श्री मजफ्फर हुसैन को १५ फरवरी, १९६४ को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें रिमाण्ड लेकर फैजाबाद जेल भेज दिया गया ।"

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : I want to know the allegations against him, and also the other details concerning the same.

Mr. Speaker : Nothing more can be said about this matter, since I was only to convey to the House the fact of his arrest.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं आवश्यक सूचना प्राप्त कर के सभा को दे दूंगा ।

हजरतबल दरगाह से पवित्र बाल की चोरी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : THEFT OF SACRED RELIC FROM HAZRATBAL

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं अब पवित्र बाल की चोरी से संबंधित सूचना उपलब्ध करने की स्थिति में हूं । इस संबंध में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकद्दमा दायर किया गया है । अभी चूंकि मामले की जांच पड़ताल जारी है इसलिये हो सकता है कि कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम भी प्रकाश

में आयें और उन पर भी मुकद्दमा चलाया जाये। अब तक यह अभियुक्त लोग गिरफ्तार किये गये हैं :

१. अब्दुल रहीम बंदे, हजरतबल के मुजावर।

२. अब्दुल रशीद, पुत्र सैयद मुहम्मद यूसु, गांव वाल।

३. गुलाम मुहम्मद बट्ट।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या सरकार इस मांग पर विचार कर रही है कि मुकद्दमा दिल्ली के किसी न्यायाधीश के सामने पेश हो और काश्मीर राज्य के न्यायाधीश के समक्ष नहीं।

श्री नन्दा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मुकद्दमे के लिये न्यायाधीश काश्मीर राज्य से नियुक्त न करके कहीं बाहर से नियुक्त किया जायगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना (निर्धारित अधिकारी) विनियम, १९६३

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): मैं (१) नौ-सेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५५ में प्रकाशित नौ-सेना (निर्धारित अधिकारी) विनियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २२५६/६४]**

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत नियम

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): मैं (२) सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उप धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २१ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५१४ में प्रकाशित सिनैमेटोग्राफ (सैंसरशिप) दूसरा संशोधन नियम, १९६३।

(दो) दिनांक ३० अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७२८ में प्रकाशित सिनेमेटोग्राफ (सैंसरशिप) तीसरा संशोधन नियम,/१९६३। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १९०८/६३]**

श्वेत-पत्र संख्या १०

वैदेशिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : मैं (३) श्वेत-पत्र संख्या १० की एक प्रति जिस में भारत और चीन की सरकारों द्वारा जुलाई, १९६३ और जनवरी, १९६४ के बीच एक दूसरे को भेजे गये टिप्पण, ज्ञापन और पत्र दिये हुये हैं, सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २२९६/६४]

केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के वार्षिक प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : मैं (४) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद, की वर्ष १९६२-६३ की वार्षिक रिपोर्ट, जो २६ अगस्त, १९६३ को टेबल पर रखी गई थी, का शुद्धिपत्र सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २२९७/६४]

राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहक उप-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON ADDRESS BY THE VICE--PRESIDENT DISCHARGING THE FUNCTIONS OF THE---PRESIDENT---contd.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): इस अभिभाषण को देख कर हमें निराशा हुई है। इस समय जब कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं ने भारत वर्ष में हलचल पैदा कर दी है, आवश्यकता इस बात की थी कि अभिभाषण में वस्तुस्थिति का चित्रण करने के साथ साथ, हौसले और समझदारी के साथ भविष्य में की जाने वाली कार्यवाहियों की चर्चा की जाती। लोगों में एक नया उत्साह पैदा किया जाता। पाकिस्तान अपने साम्राज्यवादी साथियों, ब्रिटेन और अमरीका, से मिल कर किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहा है, उस की चर्चा भी इस में नहीं की गयी। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के अल्पसंख्यकों की समस्या की गहराई को आंका ही नहीं गया। १९५० से पूर्वी पाकिस्तान में, गोपालगंज और राजशाही में और मालदा में किस प्रकार के अत्याचार हुए उस की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यही दशा वहां से आने वाले अल्प-संख्यकों को बसाने की है। जब मैंने मालदा से आने वाले आदिवासियों के पुनर्वास की बात कही थी तो बताया गया कि उन के लिये नियमों में ढील नहीं की जायगी। इसी प्रकार राजशाही के राजवंशियों और बेरुबारी गांवों के बारे में पूछने पर भी रूखा सा उत्तर दिया गया था। इस का अर्थ यही लगाया जा सकता है कि हम अल्पसंख्यकों की समस्या के बारे में तत्पर नहीं हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में इस सभा का रुख निराशाजनक है।

गृह-कार्य मंत्री ने प्रव्रजन-पत्र देने की शर्तों में ढील देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों के लिये ढील दी जा रही है। मेरा निवेदन है कि केवल कुछ वर्गों के लिये ही ढील न दे कर, जो भी वहां से आना चाहें उसे बेरोकटोक आने दिया जाय। कम से कम उन लड़कियों को, जिन के बारे में उन के मां बाप महसूस करते हैं कि वह सुरक्षित नहीं हैं, अवश्य आने दिया जाना चाहिए।

यह भी बताया गया कि जो लोग उधर से बिना प्रव्रजन-पत्र के आयेंगे उन का भी स्वागत किया जायेगा। परन्तु हमारी सीमा गेड्डी में कई लोग आये हुए हैं, उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की जा रही। जो लोग वहां से आये हैं उन्हें पाकिस्तान में छोड़ी गयी सम्पत्ति के लिये प्रतिकर नहीं दिया जाता।

दार्जीलिंग में पुनर्वास विभाग को बन्द कर देने का निर्णय लेते हुए कहा गया कि अमुक तिथि के बाद आये हुए लोगों को पुनर्वास सुविधा नहीं मिलेगी। परन्तु पूर्वी पाकि-

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

स्तान से आने वाले विस्थापितों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिये उस निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा।

हम धर्म-निपेक्षता और प्रगति की बात तो करते हैं परन्तु आज भी बस्तियों की हालत दयनीय है। कई विस्थापित मुसलमानों के मकानों में पड़े हुए हैं जिन को बदले में मकान नहीं दिये गये। उन स्त्रियों आदि से भी ऋण वसूल करने की कोशिश की जाती है जो आश्रयहीन हैं।

भारत में साम्प्रदायिक उपद्रवों का एक कारण यह भी है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका।

हम देखते हैं कि पाकिस्तान तो भारत-विरोधी प्रचार कर के हमें बदनाम करता है परन्तु हमारे नेता ब्रिटेन और अमरीका के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। वह डरते हैं कि कहीं जो सहायता हमें मिल रही है वह समाप्त न कर दी जाय। परन्तु इस विदेशी सहायता एव विनियोजन के बारे में हमें सावधान रहना होगा।

पूर्वी पाकिस्तान के साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप वहां पर अल्पसंख्यकों पर अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं किन्तु हमारी सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर पाई है। सरकार को इस बारे में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रतिदिन पूर्वी पाकिस्तान से हजारों की संख्या में जो शरणार्थी भारत आ रहे हैं उनको यहां पर फिर से बसाने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

सुरक्षा परिषद् में ब्रिटेन ने भारत के प्रति जो दष्टिकोण अपनाया है वह सर्वथा हमारी आशा के विपरीत था। सरकार ने ब्रिटेन को अपना मित्र समझा था। उसी के प्रभाव में आकर काश्मीर में युद्धविराम स्वीकार किया गया और अस्थायी रूप से जनमत संग्रह की बात चली तथा हमने काश्मीर समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपी। किन्तु ब्रिटेन ने हमारी दुर्बल नीति से लाभ उठाने के लिये ही संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाया। यद्यपि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य वैधरूप से भारत का अभिन्न अंग है, बड़े दुःख की बात है कि अब ब्रिटेन इस पर अंगुली उठा कर हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नीचा दिखाना चाहता है। काश्मीर के मामले में हमें दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। हमारी दुर्बलता से लाभ उठाने वाले देशों को हमें स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि कुछ हथियारों की सहायता के लिए हम उनके आभारी अवश्य हैं किन्तु अपनी प्रभुसत्ता तथा राष्ट्रीय गौरव का सौदा करने के लिये कदापि तैयार नहीं हैं। हमें ब्रिटेन या पाकिस्तान के अन्य मित्रों द्वारा मध्यस्थता की बात कदापि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। काश्मीर के मामले में ब्रिटेन उपनिवेशवादी नई चाल चलना चाहता है। सरकार को उसकी चाल को समझना चाहिये और यह निश्चय कर लेना चाहिए कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन भारत के हित की कोई बात नहीं कर सकता। हमें पाकिस्तान के मित्रों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि भविष्य में हम उन्हें बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं देंगे जो सदा के लिए समाप्त हो चुका है।

काश्मीर की आन्तरिक दशा बहुत खराब है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जनता का विश्वास वहां की सरकार में कतई नहीं रह गया है। भारत विरोधी तत्व काश्मीर में पाकिस्तान के लिये सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। वहां साम्प्रदायिकता की आग

भड़काई जाती है। जनता वर्तमान सरकार को बदलना चाहती है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह वर्तमान सरकार को बदल कर उसके स्थान पर काश्मीर में लोगों के पसन्द की नई सरकार बनाये।

हमें अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए साधन अवश्य जुटाय चाहिएं। यह सच है कि बिना विदेशों से सहायता लिए हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकते हैं। किन्तु इस सहयोग को किसी सीमा से अधिक बढ़ाना देश के लिये खतरे और चिन्ता की बात है। क्योंकि हमें अच्छी भांति ज्ञात है कि अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम व्यापारी के रूप में ही भारत में प्रवेश किया था और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की थी। यह चिन्ता का विषय है कि सरकार विदेशी सहायता को आंखें मूंद कर प्रोत्साहन दे रही है। यहां तक कि विदेशी सहयोग के बिना उद्योग तथा वित्त मंत्रालय लाइसेंस ही नहीं देते हैं। साथ ही सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में भी विदेशी पंजी को बढ़ावा दे रही है। गैर-सरकारी क्षेत्रों में विदेशी पंजी पर होने वाले लाभ का भारी अंश विदेशों को चला जाता है। तेल, इस्पात और लौह अयस्क के उत्पादन में भी विदेशी पूंजी को ही अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। सरकार को भविष्य में संभावित परिणामों को ध्यान में रख कर विदेशी सहयोग पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिये। स्वावलम्बी होना ही सब से अधिक सम्मान की बात है।

खाद्यान्नों के, विशेष रूप से चावल के, मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। भुवनेश्वर में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया था कि चावल की मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। किन्तु यह खेद की बात है कि इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है।

आज देश में भ्रष्टाचार जोरों पर है। उदाहरण के लिये कलकत्ता में एक इंजीनियरी फर्म में पुलिस द्वारा छापा मार कर बहुत से कागजात पकड़े गये जिनको देखने से पता चला कि इस फर्म की एक शाखा बिना सरकार की अनुमति के लंदन में काम कर रही है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यदि सरकार वास्तव में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है तो सब से पहले उसे भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। आर्थिक विषमताओं को घटाना होगा तथा पूंजीवाद का अन्त करना होगा।

Shri R. G. Dubey (Bijapur North): Mr. Speaker, migration conditions should be relaxed for those of the minority community in Pakistan who want to come to India. The policy of the Government in this regard is correct. The basic thing that one has to bear in mind in this matter is that Muslims living in India are Indian Nationals and similarly Hindus of Pakistan are the nationals of that country. The Government have been trying to create an atmosphere in which they may feel secure and may live in their own homes. Efforts should be made to rehabilitate the refugees coming from East Pakistan without disturbing our national economy.

Dr. Lohia and other hon. Members want the release of Sheikh Abdullah and at the same time they ask for firm stand in regard to Kashmir. Thus they are putting forth two contradictory proposals before the Government. Kashmir is an integral part of India and there is no question to hand it over to Pakistan at any cost.

[Shri R. G. Dubey]

The question of massacre of thousands of people belonging to minority community in East Pakistan and infiltration by Pakistanis into Assam and other places should be made known to all countries. We cannot tolerate the inhuman treatment meted out to minorities by Pakistan. Proper assessment should be made of the actual number of Pakistani infiltrators into Assam. Effort should also be made to create world opinion against Pakistan in regard to the treatment which minorites are receiving there. We should take effective steps to deal with Pakistan. If we fail to do that it will have disasterous effects on our country.

Mention has been made in the Address that despite some progress made in the field of industry, the economic condition of our country is not satisfactory. Little progress has been made in agricultural production. Government should pay greater attention towards production and prices. We have been trying to increase our production for the last several years but no fruitful results could be achieved. The main reason of this failure is that there is no sincerity on the part of the administration to implement the various schemes effectively. The officers responsible for implementing these schemes, believe more in paper work than in actual development work. Now it is proper time that we should launch a movement on a mass scale to increase our production in every field. People entrusted with the responsibility of implementing our plans should be made to work honestly and efficiently.

We are spending about Rs. 150 crores per year on the import of foodgrains to meet our requirements. It is better if the Government spend rupees fifty crores only on the import of tractors and their components. Steps should also be taken to manufacture tractors in our country. Agriculturists should be given every possible assistance and incentives in order to increase the production of foodgrains. Modern scientific methods of cultivation should be adopted by the agriculturists.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy-Speaker in the chair]

श्री ब्रज प्रकाश ([illegible]): अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के लिये हम उपराष्ट्रपति के आभारी हैं और उन्हें बधाई देते हैं। देश में जो कुछ विकास कार्य हुए हैं उसके लिये हमें गर्व है। उपराष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में प्रजातांत्रिक और समाजवादी समाज की चर्चा की है। हम ने इस उद्देश्य को पाने के लिए बहुत पहले निर्णय किया था किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हम इस ओर तीव्रता से अग्रसर नहीं हो रहे हैं। हमारी योजनाओं में कृषि की अपेक्षा अन्य विकास संबंधी कार्यों को अधिक महत्व दिया गया है जिस के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार को चाहिए कि वह इस कार्य के लिए आवश्यक वित्त और उपयुक्त संगठन की व्यवस्था करे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कृषकों को उपज के उचित मूल्य प्राप्त हों। अब समय आ गया है जब आवश्यक कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित किये जाने चाहियें। अत्यावश्यक कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों का व्यापार सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए जिस से उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हो सके।

लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। वास्तव में यदि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो कुछ गिने हुए लोगों को, समस्त समुदाय को हानि पहुंचा कर, अपनी तिजोरियां भरने का अवसर नहीं देना चाहिए। यदि धन कुछ ही लोगों के हाथों में चला जायेगा तो धनी और अधिक धनी तथा निर्धन और अधिक निर्धन होता जायेगा। इस

प्रकार समाज में विषमता बढ़ेगी। इसका कोई हल सरकार को निकालना ही चाहिये।

सहकारी क्षेत्र को एक ओर तो सरकारी क्षेत्र और दूसरी ओर गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा से हानि होती है। इसलिये इसे रोका जाना चाहिये। सहकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये अत्याधिक सतर्कता की आवश्यकता है। हम निम्न-स्तर पर लोगों को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हैं और यह भूल जाते हैं कि ऊंचे स्तर पर भी बहुत भ्रष्टाचार विद्यमान है। सरकार को भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए कम से कम दो आवश्यक कदम उठाने चाहियें। पहला कदम यह कि प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति, चाहे उसका किसी दल से संबंध हो, जिस में मंत्री भी शामिल हैं, धनाढ्य लोगों का आतिथ्य स्वीकार न करें, और दूसरा यह कि भारत सरकार के किसी कर्मचारी को गैर-सरकारी समवायों में कार्य करने की स्वीकृति न दी जाये।

काश्मीर का भारत में विलय करने में हमने विलम्ब किया है। काश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के स्तर पर यथा शीघ्र लाया जाना चाहिये। इसके बाद जनता में सरकार के प्रति पुनः विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक, तथा अन्य कदम उठाये जाने चाहिएं। शेख अब्दुल्ला के जिस पर भारत के प्रति षड़यंत्र का दोष है—मुकदमे की सुनवायी काश्मीर से बाहर अन्य किसी राज्य में होनी चाहिए जिस से लोगों में विश्वास पैदा हो सके।

बड़े खेद की बात है कि अभिभाषण में दिल्ली की भावी प्रशासन व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं की गई है। दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या लगभग २६ लाख है और आगामी २० वर्षों में ५० लाख हो जायेगी। दिल्ली की समस्याये बढ़ती जा रही हैं और सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। संघ राज्य क्षेत्र संबंधी विधेयक पर विचार करते समय प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि भारत सरकार दिल्ली प्रशासन के बारे में विशेष रूप से विचार कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता है जो दिल्ली प्रशासन के लिये उत्तरदायी समझा जा सके। दिल्ली निगम अपने उत्तर दायित्वों को निभाने में सर्वथा असफल रहा है जिससे दिल्ली के नागरिकों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। दिल्ली निगम, दिल्ली प्रशासन तथा भारत सरकार में कोई समन्वय नहीं है जिस से कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। इस प्रकार वस्तु स्थिति बिगड़ गयी है। भारत सरकार को दिल्ली के भावी राजनैतिक ढांचे के बारे में भी यथा शीघ्र निर्णय करना चाहिए।

मुझे आशा है कि सरकार इस पर शीघ्र कुछ निर्णय करेगी क्योंकि यह मामला बहुत दिनों से अनिर्णीत पड़ा है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Government have adopted a policy of drift towards our national problems and the Country is leading towards chaos and disaster.

Shri Dubey has stated in his speech that the Government should take a firm stand on Kashmir issue. All of us want, that Kashmir should not be surrendered to Pakistan at any cost. The question of Kashmir as well as other problems between India and Pakistan can be solved, if they both join a Confederation because they were one country only 16 years back.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

Mr. Dubey has also mentioned in his speech that there can be no solution to the problem of rising prices unless supply keeps pace with demand. The Prime Minister has, also, admitted in his statement that rising prices cannot be checked for about 15 years to come. This is a great failure on the part of the government. The prices of foodgrains, particularly of wheat, in Delhi have gone up by 50 per cent since the last harvest and will go up still further in the ensuing months. Thus, the traders are earning huge profits and both producers and consumers are suffering due to abnormal increase in prices. There should be a rule whereby there should not be an increase of more than one anna a seer of foodgrains during the whole crop year. Opening few fair price shops is no solution of the problem.

Unless Government deals with the problem of language, casteism,starvation, famine, inequality etc. individually industrialisation cannot take place in the real sense. The Congress Party has no policy and no leadership. I would like to tell my friend ShriDubey that I have not said that the fate of India is in wrong hands. I said that the leadership is not good. During the last fifteen years problem after problem has cropped up and none has been solved. I would ask hon. Members to cite a single instance, where solution has been found.

In the Address it has been said that various steps have been taken to bring about efficiency in our Army and Air Force. Further it says that conditions of service & pension have been improved. But by improving service conditions we cannot revitalise the armed forces. Every human aspect of the problem should be taken into account besides improvements in financial and service conditions.

The reverses in Nefa were a result of wrong direction. The Indian forces were nowhere engaged in real combat. Only in Walong the fighting lasted for one and a half days. Three persons were responsible for the Nefa debacle —Prime Minister Nehru, Mr. Krishna Menon, the then Defence Minister and Lt. General—Kaul. Either they are collectively responsible for it or in groups of two or individually. I demand an enquiry into this matter. Unless a thorough enquiry is conducted into it the army cannot be made strong. The post of Prime Minister should be held by a man who holds the interest of the country in the highest esteem, and does whatever is needful for the country. A question should be looked at from the angle of an Indian and not from any other angle. All these problems are before us because Indians by nature are not aggressive. Unless the people of the country rise in revolt against the internal enemy, these problems will remain as they are and the standard of army cannot be improved. But the Indian history of the last 1500 years is a witness, to the fact that we have not learnt to fight the internal enemy.

When we talk of stability it is said that government has given stability to the country. Examples are cited of the countries where uprisings have taken place. Personally I like unstability and uprisings because it activales the inactibe But I want to draw attention of another kind of unstability. Let us assume that there is stability so far as Central Government is concerned. But see the State Governments. There is unstablity when the ruling party and the opposition stand on equal footing. That kind of unstabiity is good, because that is instrumental in setting things right. But the fact that there are dissensions within the ruling party is not conducive to the wellbeing of the country. I want to say that there has come an explosive unstability in the State Governments.

There has been talk of a Central Vigilance Commission to go into cases of Coruption.I want the rigilance Commission to go into the grants given to caps funds and trusts held by the Prime Minister. The alone I can think that the Commission really wants to put an end to corruption otherwise not. Some people say that I should not criticise the Prime Minister as he is ill. But I want to pinpoint the fact that when he cannot give a good lead to the country in perfect health how can we expect a better lead from him when he is not well.

Now I come to science as it has been mentioned in the Address. I want to know the achievements of the Indian scientists during the last 15 years. In other countries the first place is of the scientist, the second of implements and then laboratory. But here in our country the order is the reverse. The scientist is devoid of brain. He has nothing to fear because of some relation who wields power in the Government.

I believe in action. Therefore I want action to be introduced in our economic and foreign affairs policy. But now fate has the upper hand and not the action.

Mention has been made of Nepal. In this connection I want to say that leading members of the public have been put behind the bars there. Bhutan and Sikkim should not be referred as if they are separate entities at last in so far as the foreign policy is concerned.

It has been said in the Address that we are making advancements towards peace. But if an atomic test ban treaty has been signed between the U.S.A. and U.S.S.R. it does not help India. What kind of peace you have achieved so far as problems in regard to Pakistan, Kashmir, Bengal and China are concerned.

This morning a telegram has been received regardingthe arrest of Shri Muzaffar Hussain. I do admit that he said something wrong but on that ground he should not have been arrested. It is not democracy if a man cannot express himself freely.

In the end I cannot help saying that reports are reaching me that 30,000 persons were killed in East Pakistan and about 2000 villages were set on fire. Therefore some remedy should be found out to put a stop to this kind of thing. Therein lies the welfare of the country.

श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर): उपराष्ट्रपति का अभिभाषण अल्पसंख्यक वर्ग के लिये विशेषकर महत्वपूर्ण है। यह शायद पहला अवसर है कि अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति देश के सब से ऊंचे पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। बहुसंख्यक वर्ग इसके लिये बधाई का पात्र है। उप-राष्ट्रपति भी देश की बधाई के पात्र हैं कि राष्ट्रपति के पद से उन्हें भारतीय संसद् को अपना अभिभाषण देने का अवसर मिला।

भारत मे अल्प संख्यक वर्ग के लिये जो कुछ किया जा रहा है इतना विश्व के कसी देश मे नहीं कया गया है। नागालैंड राज्य की स्थापना कर दी गई है तथा हिमाचल प्रदेश मनीपुर, त्रिपुरा, तथा गोआ मे विधान सभायें कायम कर दी गई हैं। मुझे मालूम है कि सरकार आसाम की पहाड़ी जातियों तथा नेफा के लोगों की मांग को पूरा करने पर विचार कर रही है।

[श्री रिशांग किशिंग]

पूर्वी पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों से बहुत से आदिवासी आसाम में आ गये हैं। मैं सरकार से अनरोध करूंगा कि उनको उपयुक्त क्षेत्रों में बसाया जाये जहां का वातावरण उन के अनकूल हो। सीमान्त क्षेत्रों में स्थिति विशेषकर चीनी आक्रमण के कारण काफी जटिल हो गई है। पास्किस्तान तथा चीन इस देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। हमें किसी भी विकट से विकट स्थिति के लिये तैयार रहना चाहिये। आसाम तथा नेफा की पहाड़ी जातियों की समस्या को शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिये। वहां पर समाजविरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी तत्व विदेशों के एजेंट के रूप में कार्य करते रहते हैं। वे बाहर से चोरी छिपे हथियार लाते हैं और देशविरोधी कार्यो के लिये इनका इस्तेमाल करते हैं। प्रमुख स्थानीय व्यक्तियों अथवा देशभक्त व्यक्तियों को उनसे खतरा बना रहाता है। अतः वहां पर सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये। उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाया जाये। वहां पर सशस्त्र पुलिस में भी वृद्धि की जानी चाहिये। चूंकि सशस्त्र पुलिस में स्थानीय व्यक्ति अधिक होते हैं इसलिए वे उन क्षेत्रों के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। अतः वे समाज-विरोधी तत्वों को खत्म करने में अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। देशभक्त नागरिकों के संरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। वहां की शत प्रतिशत जनता यह चाहती है कि वहां पर स्कूल खोले जायें। अतः सरकार को उस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिये। उच्च शिक्षा का भी वहां पर उपबन्ध किया जाना चाहिये। प्रत्येक ब्लाक में एक हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा प्रत्येक जिले में एक कालिज की स्थापना की जानी चाहिये। वहां पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। वहां पर लोगों को शिक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी के माध्यम से दी जानी चाहिये।

यहां पर आपातकाल को समाप्त करने की मांग की गई है परन्तु मेरा निवेदन है कि सीमान्त प्रदेशों में आपातकाल की स्थिति को बनाये रखा जाये ताकि राष्ट्रविरोधी तत्वों को दबा कर रखा जा सके।

देश में भ्रष्टाचार खूब जोरों पर है। मैं तो कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में विकास निधि का २५ प्रतिशत भाग भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जाता है। योजना की असफलता के लिए भ्रष्टाचार ही जिम्मेदार है। इसे समाप्त करने के लिए हर प्रयत्न किया जाना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति का स्वागत करता हूं। भ्रष्टाचार को हर स्तर पर समाप्त करने के लिये कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं चाहूंगा कि संघ राज्य क्षेत्रों में भ्रष्ट चार विरोधी समितियां तुरन्त नियुक्त की जानी चाहियें।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री ट० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : यदि हम लोकतन्त्र को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ मूल सिद्धान्तों को मानना होगा। इसके लिए हमें मताधिकार के महत्व तथा संसद् की प्रभुसत्ता को स्वीकार करना होगा। विधियों का पालन करके ही हम देश में शांति बनाये रख सकते हैं। जहां तक समाजवाद का सम्बन्ध है हम शांतिपूर्ण ढंग से समाजवाद लाना चाहते हैं। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाये जा चुके हैं।

मुझे डर है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में हम योजना अवधि के अन्त तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगे। सिचाई से हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। परन्तु सिंचाई साधनों का लाभ नहीं

उठाया जा रहा है। मैसूर की योजना में बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए ४०·७ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था परन्तु अभी तक इस पर २० करोड़ रुपया व्यय किया गया है। सिंचाई का पूर्ण उपयोग करने के लिये अधिक उपबन्ध किये जाने की आवश्यकता है। मैसूर में छोटी सिंचाई योजनायें ठीक तरह से प्रगति कर रही हैं। अतः मैसूर को आगामी वर्ष के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिये। इसके साथ साथ हमें उवर्रक का उत्पादन की भी बढ़ाना चाहिये। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में इस बारे में प्रगति धीमी है तो सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें। सहकारी समितियों को चीनी के कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये जाने चाहियें।

बेल्लारी-हासपेट क्षेत्र में एक इस्पात कारखाना लगाया जाना चाहिये क्योंकि वहां पर कच्चा लोहा अधिक मात्रा में उपलब्ध है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि मैसूर राज्य में एल्यूमिनियम का कारखाना स्थापित किया जाये।

पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारी संख्या में भारत में प्रवेश करने के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया है। यह खेद की बात है कि ब्रिटिश प्रतिनिधि ने भी पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया है और उन्होंने काश्मीर के बिलय के प्रश्न के फिर से उठाये जाने की भी मांग की है। हमें ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि हम ऐसी बातें सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि बाह्य अन्तरिक्ष में परमाणु अस्त्रों के परीक्षण न करने के बारे में संधि हो गई है। विश्व में तनाव को कम करने में हमारे प्रधान मंत्री का प्रमुख हाथ रहा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सब से पहले मैं राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। प्रधान मंत्री का नेतृत्व भारतीय गणतन्त्र के लिए इतना ही मूल्यवान है जितना कि कांग्रेस के लिये। उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्त राष्ट्र चिन्तित है। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रधान मंत्री के बोझ को हल्का किया जाये। परन्तु उप-प्रधान का नियुक्त किया जाना मेरी राय में एक प्रतिगामी कदम है। आवश्यकता इस बात की है कि एक शक्तिशाली तथा सक्षम सामूहिक नेतृत्व को जन्म दिया जाये। प्रधान मंत्री ऐसे नेतृत्व की स्थापना में सहयोग दे सकते हैं। ट्रोइका शासन पद्धति के अन्तर्गत भी सामूहिक उत्तरदायित्व तथा सामुहिक कार्यकरण के सिद्धांत को ठेस पहुंची है। विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय बहुत कम है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि पटसन तथा वस्त्र विभाग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय से क्यों छीने गये हैं जब कि वह मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि सम्बन्धी नीतियों को अधिक सुचारू रूप से कार्यान्वित करने की स्थिति में है। मैं जानना चाहता हूं कि समन्वय को जानबूझ कर दुर्बल बनाने के अनेक प्रयत्नों में से यह केवल एक प्रयत्न है। भारतीय जुट मिल संस्था के साथ कार्यकरण-समय सम्बन्धी समझौते के समाप्त किये जाने पर भी मझे आपत्ति है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय अब कार्य कर रहा है या नहीं।

तृतीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन में वाले यह बताया गया है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके हैं। वादविवाद का उत्तर देने वाले मंत्री महोदय को सभा को यह बताना होगा कि योजना में असंभव लक्ष्यों को क्यों रखा गया है। जब कार्यान्विति की बात आती है तो कह दिया जाता है कि हम ऐसा नहीं कर पाये हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि योजना का वार्षिक मूल्यांकन किया जाना चाहिये तथा देश को उस बात के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये जो हम सब के लिये महत्वपूर्ण है।

मैं इस प्रसंग में राजस्थान में विद्यमान अकाल स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। लोगों से मेरे व्यक्तिगत सम्पर्क से मुझे ज्ञात हुआ है कि उनकी दशा को सुधारने के लिए अधिक प्रयत्न नहीं किये गये हैं। १६ वर्षों के व्यतीत होने के बावजूद भी सरकार फसलों को मौसम की खराबी के कारण नष्ट होने से बचाने में असमर्थ रही है। जब तक सरकार राजस्थान जैसे प्रदेशों की जहां लोगों की दशा दयनीय है, स्थिति में सुधार करने के लिए भारी प्रयास नहीं करेगी, समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता।

राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश की समस्याओं के लिए मैंने सदन में कई बार रेगिस्तान विकास प्राधिकार जैसे एक निकाय की स्थापना का सुझाव दिया है। यह निकाय उस क्षेत्र के विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को समन्वित करने में सहायक होगा। इन समस्याओं को तत्काल हल किया जाना चाहिये।

नौकरशाही लोकतंत्र का नाश कर रही है। भ्रष्टाचार आम है, सतर्कता आयोग की बात स्वागत योग्य है। परन्तु हमारे गृह-कार्य मंत्री अबंडजमन जैसी व्यवस्था करने के पक्ष में क्यों नहीं हैं। श्री नन्दा ने दो वर्षों में भ्रष्टाचार दूर करने का प्रण लिया था, क्या वह अपने प्रण पर कायम हैं। यदि वह अपना प्रण पूरा करने में असफल रहे तो क्या होगा? भ्रष्टाचार के बीज तो बहुत गहरे हो गये हैं। कामराज योजना इस का कोई उपचार नहीं। जरूरत इस बात की है कि सरकार राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाये। इस समय देश में आपात स्थिति को जारी रखने का कोई लाभ नहीं।

इस बात को देखते हुए कि आज समस्त संसार में हम मित्र विहीन हो रहे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को मजबुत करना चाहिये। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिये कि हमारी सीमा की सुरक्षा ठीक ढंग से हो। सीमा क्षेत्रों की देखभाल अच्छी प्रकार से की जानी चाहिये। यह भी आशा करनी चाहिये कि सरकार रचनात्मक बातों और सुझावों की ओर समुचित ध्यान देगी।

श्री प्रिय गुप्त : मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं * * *

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, जो कुछ कहा गया है उसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : उपराष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू विस्थापितों की समस्या हमारी राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। परन्तु इस समस्या में उलझे रह कर हमें आसाम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के अवैध प्रवेश की समस्या को कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिये। इससे भारत की सुरक्षा को खतरा है और इस अवैध प्रवेश को रोकने की हर तरह से कोशिश की जानी चाहिये।

इस समस्या को दो तरीकों से हल किया जा सकता है। पहला यह कि सीमावर्ती राज्यों अर्थात् पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और आसाम में सीमा सुरक्षा खंड की स्थापना की जानी चाहिये जिसमें सीमा से २० मील दूर तक का क्षेत्र शामिल किया जाना चाहिये और उन क्षेत्रों में रहने

***कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाले सब मुसलमानों को देश के अन्य भागों में बसाया जाना चाहिये। दूसरे यह कि उन सीमावर्ती राज्यों में जहां मुसलमान अधिक संख्या में रह रहे हैं वहां मुसलमान घरानों का अनिवार्यतः पंजीयन किया जाना चाहिये और अवैध प्रवेश करने वालों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा अक्सर जांच पड़ताल कराई जानी चाहिये।

पाकिस्तान सरकार की नीतियों के फलस्वरूप हिन्दुओं के लिए पूर्वी पाकिस्तान में रहना असम्भव हो गया है। योजना आयोग को चाहिये कि वह पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के क्रमबद्ध प्रव्रजन और पुनः संस्थापन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था करे। आसाम के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए मुसलमानों के अवैध प्रवेश को रोकने और हिन्दू शरणार्थियों को बसाने की समस्याओं के हल के लिए सक्रिय कार्यवाही करनी होगी। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों की सम्पत्ति की हानि के लिए भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार से प्रतिकर की मांग करनी चाहिये। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि इस मामले को लेकर सरदार पटेल ने पाकिस्तन से भूमि भी मांगी थी। आशा करनी चाहिये कि सरकार इस दिशा में उचित कदम उठायेगी।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओं पर अपने अभिभाषण में प्रकाश डाला है, जिन को हल करके हम अपने लोकतंत्रीय समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शांति और सहयोग के इच्छुक हैं। उपराष्ट्रपति महोदय ने कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया है और उन्हें हम मिल कर हल कर सकते हैं; सफलता प्राप्त करने का एक मात्र साधन यही है कि उत्पादन बढ़ाया जाये जब तक यह नहीं होगा तब तक कठिनाइयां दूर नहीं हो पायेंगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों का प्रोत्साहन करना आवश्यक है, उनके लिए उचित मूल्य सुनिश्चित किये जाने चाहियें।

केरल में काली-मिर्च, हल्दी, इलायची का उत्पादन होता है जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यदि उनका उत्पादन बढ़ाना है तो उनके निम्नतम निश्चित कर दिये जाने चाहियें। सरकार को केरल में बिजली की सप्लाई की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिये। केरल में बिजली की सप्लाई अक्सर रुक जाती है जिससे उद्योगों के लिए बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं बेहतर होगा कि वहां कुछ थर्मल स्टेशन स्थापित किये जायें।

यह बात बिल्कुल गलत है कि केरल और कुछ अन्य राज्यों में लोकतंत्र नहीं चल रहा है और वहां विधि और व्यवस्था भंग हो गई है केवल इस आधार पर एक मंत्री का त्यागपत्र मांगना उचित नहीं था कि मोटर गाड़ी एक्ट के अन्तर्गत उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया था ऐसा इसलिए किया गया कि पुलिस उचित प्रकार से मामले की छानबीन कर सके तथा अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। कोई नहीं जानता कि किसी प्रजातन्त्रीय तन्त्र में और क्या किया जा सकता है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, सरकार इस बारे में स्थिति को जानती है तथा विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। परन्तु उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध निराधार आरोप लगाने की मनोवृत्ति को रोका जाना चाहिये।

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : सुरक्षा परिषद् में ब्रिटन के प्रतिनिधि ने जो भाषण दिया है, उससे सारे भारत को परेशानी हुई है। मेरा निवेदन है कि इस क्षोभ को देखते हुए हम

अपने सामने आये खतरे को महसूस करें। और हमारी सरकार को बड़ी दृढ़तापूर्वक तथा असंदिग्ध प्रकार से घोषणा कर देनी चाहिये कि ब्रिटेन और अमरीका के लोगों को काश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं है। खेद की बात है कि अंग्रेज भारत के प्रति अपने रवैये को ठीक सिद्ध कर रहे हैं, इससे मामला और भी गम्भीर हो जाता है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि सुरक्षा परिषद् में लोकमत जानने का जो प्रस्ताव रखा गया है वह एक बड़ा भारी खतरा है। इससे एक जाल बिछाने का प्रयत्न किया गया है जिससे भारत और उसके समर्थक अपनी मूल नीति को छोड़ कर अन्य दृष्टिकोण अपनाने पर मजबूर हो जायें।

यह तो बड़ी स्पष्ट बात है कि पाकिस्तान सरकार एक निश्चित लक्ष्य से पाकिस्तान में सामयिक गड़बड़ पैदा करके वहां साम्प्रदायिक दंगे करा देती है। पूर्वी बंगाल में यह आन्दोलन चल रहा है कि देश में लोकतंत्रीय प्रशासन समाप्त हो। वहां के लोग सैनिक तानाशाही से काफी तंग हैं और इसे समाप्त कर देने के इच्छुक हैं। काश्मीर के मामले की आड़ लेकर इस आन्दोलन को अच्छे प्रकार से सुविधापूर्वक समय समय पर दबा दिया जाता है। ऐसा करने से लोगों का ध्यान दूसरी ओर चला जाता है। श्री चागला ने जिस प्रकार पाकिस्तान को नंगा किया है, उसके लिये मैं उन्हें अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करता हूं। हमें काश्मीर के मामले में स्वर्गीय डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी के बलिदान को नहीं भूलना चहिये। हमारे मंत्री को यह घोषणा कर देनी चाहिये कि काश्मीर का भारत से विलय हो चुका है, और इस बात पर कोई बातचीत करने क प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। काश्मीर की आन्तरिक स्थिति भारत का घरेलू मामला है और इस मामले में किसी विदेशी शक्ति को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हमने अनुच्छेद ३७० को संविधान में सम्मिलित करके ठीक नहीं किया था। काश्मीर का भारत में सम्मिलित होना एक अन्तिम तथा अभिभंगनीय मामला है। इसमें अब मध्यस्थता, समझौते तथा लोकमत संग्रह का कोई प्रयत्न ही नहीं उत्पन्न होता। हमने काश्मीर में लोकतंत्रीय ढंग से कराये हैं, और हर बार वहां के लोगों ने पूर्ण रूप से सहमत हो कर यह निर्णय दिया है कि वे भारत के साथ हैं। इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करूंगा कि काश्मीर के बारे में अनुच्छेद ३७० को समाप्त कर दिया जाय। संविधान के उपबन्धों को हटा कर काश्मीर को भारत का अभिन्न खंड करार दिया जाय। इस राज्य की बदनाम सरकार को हटा कर सभी दलों की मिली जुली लोकतंत्रीय सरकार की स्थापना दी जानी चाहिये। यदि हमारी सरकार इस मामले में स्पष्ट घोषणा करे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के सभी वर्ग, दल और नागरिक उसका पूर्णतः एक मत से समर्थन करेंगे।

Shri Samnani (Jammu & Kashmir)) : Mr Chatterjee and other friends have expressed their views regarding the stand taken by the U. K. delegate in the security Council. It is a fact that every Indian has been shocked by that attitude, but this is not new thing and it should not surprise us at all. This has been their policy since long.

In this connection, I have to make an humble request that we should be very careful in commenting on the Kashmir affairs. The situation is so serious that any comment made on the basis of wrong and incorrect information can lead us to disaster. It is liable to help the enemy. It was unfair to make all sorts of allegations against the Jammu and Kashmir Govt. I really feel shocked at the remarks of shrimati Renu Chakarverty that Bakshi Gulam Mohammad

is corrupt. It is the same Bakshi Gulam Mohammad who was the hero of the party in power there upto 1963.

There is a history behind the holy relic, but the incident involving the loss of holy relic was very unfortunate. Much more unfortunate is the attitude of certain people who tried to make political capital out of it. And it is all the more unfortunate that they received help also from some quarters. The so-called Action Committee was formed, whose duty was to help in recovery of the relic. But when the relic was found, there is no justification for this Action Committee to continue functioning. Now the genuineness of the relic has also been established, and it has been restored in original place.

Now comes the question of closer integration. It is stated that we are against it. I want to tell this to all concerned that Kashmir has been the part and parcel of India right from its inception. Kashmir's relation with India dates back from time immemorial. Kashmir spread the light of learning in distant places and produced prolific scholars. People from south India and the other parts of the country came to Kashmir in quest of the knowledge and literature. Both India and Kashmir had the impact of each other on them. Then came the Mugal rule, Afghan rule and the rule of several Kings. Then the time came when the people in Kashmir rose against the One man's rule. And in that struggle the majority community had to play its role. And this agitation in Kashmir in 1931, 1932 and 1933 was fought in the name of the Muslim Conference.

The Muslim Conference, I may state, in Kashmir has been inspired by the conference and ultimately changed its name and policy, and get the association, cooperation and support of all communities in the State. But on the advice of the national leaders it had kept its identity separate from the Congress. And it changed the nomenclature into National Conference. The National Conference has always stood and suffered for the national cause. The proof of it was furnished by the fact that when Sheikh Abdullah was going astray from the national path, it immediately forsook him. The national forces in Kashmir had always been embodied in National Conference. And it is always alert to see that reactionary and communal elements may not disrupt the national forces.

Kashmir is a part of India has been decided by the will of the people. There has been three free elections in Kashmir which have amply demonstrated this fact that people of the state were with India, body and soul. There should not be any doubts on this issue. I may be allowed to state the fact that those who now called the Bakshi Regime the Corrupt Regime, had remained silent all the years from 1954 to 1963, while he was the Prime Minister of the state. But when he relinquished his office under Kamraj plan the charges have begun coming. In my opinion these charges are unbecoming. One thing should be understood that if Kashmir goes, India will also go.

†**श्री पु० र० पटेल** (पटना) :

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुई
Dr. Sarojini Mahishi *in the Chair*]

उपराष्ट्रपति महोदय ने युगान्डा और केनिया ने जो हाल ही में स्वतन्त्रता प्राप्त की है। हमें इस बात का हर्ष है कि अफ्रीका के इस हिस्से को आजादी मिली है। आज उपनिवेशवाद के दिन समाप्त हो गये हैं। परन्तु स्वतन्त्रता के बाद वहां के भारतीयों की दशा बहुत खराब हो गई है। इस ओर हमें सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना है। मेरा निवेदन है वहां के भारतीयों के हितों की रक्षा की ओर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि

2202 (Ai) LSD—7.

उन्हें भारत वापिस आने पर मजबूर किया जाता है तो उनको अपने सामान के साथ पहुंचने पर सीमा शुल्क के मामले पर समुचित रियायतें अवश्य दी जानी चाहियें ।

उप-राष्ट्रपति महोदय ने हजरत बल दरगाह से पवित्र बाल की चोरी हो जाने के मामले का उल्लेख किया है। हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लनी चाहिये कि ये हजरत बल दरगाह से पवित्र बाल और मन्दिरों से कुछ मूर्तियों की चोरी पाकिस्तान के भीषण षड़यन्त्र का परिणाम है। उनका वास्तविक उद्दश्य तो साम्प्रदायिक आग को भड़काना था । परन्तु जब साम्प्रदायिक आग न भड़क सकी तो पाकिस्तान के कर्णधारों ने पूर्वी पाकिस्तान में दंगे करवा दिये। वहां २०,००० से ऊपर हिन्दू मार डाले गये। सैकड़ों का अपहरण हुआ और गांव के गांव जला दिये गये। यह सब पूर्वी पाकिस्तान में हुआ परन्तु इस ओर हमने किसी प्रकार से गुंडापन नहीं पनपने दिया । मेरा मत है कि अब हमें शक्तिशाली होना चाहिये ।

काश्मीर के मामले में तो हमें यह समझ लेना चाहिये कि यह तयशुदा बात है कि काश्मीर हमारा है, भारत का अंग है। इस दृष्टि से वहां जो भी गड़बड़ अथवा अतिक्रमण हो उसका मुकाबला किया ही जाना चाहिये। हमें कोई कमजोरी नहीं दिखानी चाहिये। इस कमजोरी के कारण ही हम संसार में अपने मित्र खो रहे हैं। सुरक्षा परिषद् में ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जो रवैया अपनाया वह बहुत ही लज्जाजनक था, ब्रिटेन को उस पर विचार करना चाहिये । इस बारे में मुझे यह भी शिकायत है कि लंदन में बैठे हुए हमारे उच्चायुक्त भी कुछ नहीं करते। हमारे वहां के प्रतिनिधियों ने इस मामले में हमें यह भी सूचना नहीं दी कि वहां की सरकार की नीति में परिवर्तन आ रहा है। इस संदर्भ में मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे अपमान सहन नहीं करना चाहिये। उसे दृढ़ता से काम लेना चाहिये। यदि युद्ध भी करना पड़े तो चिन्ता नहीं करनी चाहिये। हमें ताकतवर बन कर नेफा की हारों का बदला लेना ही चाहिये ।

आज की स्थिति में हमें सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर को भूल जाना चाहिये। इस बात को नहीं उठाना चाहिये कि अमुक उद्योग सरकारी क्षेत्र में और अमुक गैर-सरकारी क्षेत्र में। हमें उद्योग और कृषि उत्पादन की अधिकतम व्यवस्था करने में लग जाना चाहिये। इस काम में हमें सारी शक्ति लगानी चाहिये। हमारे उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कृषि उत्पादन सन्तोषजनक नहीं रहा है। यह बात ठीक है कि देश में कृषि की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ रही हैं इसका कारण यह है कि देश के किसानों को उपयुक्त अपेक्षित साधन और सुविधायें प्राप्त नहीं हो रहे।

इस संदर्भ में मझे यह भी निवेदन करना है कि हमारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय अधिक उत्पादन की ओर इतना ध्यान नहीं दे रहा, जितना यह प्रयत्न करता है कि अनाज बाहर से मंगवाया जाय। खाद्यान्नों तथा गुड़ इत्यादि पर लाने ले जाने पर पाबन्दियां लगा देने से कुछ मध्यवर्त्तियों को ही लाभ हो सकता है। इन पाबंदियों का यह परिणाम हुआ है कि उत्पादकों को तो दाम कम मिले और उपभोक्ताओं को बहुत अधिक दाम देने पड़े। हापुड़ में तो गुड़ का दाम २० रुपये मन है और गुजरात में यह ७५ से ६० रुपये मन तक बिक रहा है। इससे किस को लाभ पहुंचा। गुजरात के गरीब लोगों को अधिक दाम देने पड़े। कृषि मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिये।

†**डा० ब० ना० सिंह** (हजारीबाग) : मैं माननीय उपराष्ट्रपति के प्रति उनके अभिभाषण के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं । परन्तु मैं नेहरू सरकार की नीतियों से सहमति प्रकट नहीं कर सकता । सरकार के केवल मात्र शब्दों से देश की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकेगा । आज कामराज योजना के बाद हमारे मंत्री गण बहुत आत्म तुष्टि की स्थिति में रह रहे हैं और उनका व्यवहार जनता की कठिनाइयों के प्रति नितान्त उपेक्षा का है । ऐसा लगता है कि आज कल वे सब यह सोचने में लग रहे हैं कि नेहरू के बाद कौन देश का सर्वेसर्वा बनेगा । इस बारे में मेरा मत यह है कि प्रधान मंत्री द्वारा तीन व्यक्तियों के नियुक्त किये जाने से शासन की स्थिति और भी खराब हो गई है । मेरा निवेदन है कि इस बारे में प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है ।

उपराष्ट्रपति के अभिभाषण में कटु बातों को बड़ मधुर शब्दों में कहा गया है । गत १६ बरस से सरकार की अस्पष्ट नीति ने देश का काफी अहित किया है । आवाड़ी से भुवनेश्वर तक आते आते इन लोगों के समाजवाद का रूप बिगड़ गया है । समाजवादी सहकारी राष्ट्र मंडल, राज्य, समाज वादी समाज की व्यवस्था पर आधारित, 'लोकतंत्रीय समाजावद इस तरह की कई आवाजें सुनाई देती हैं । परन्तु वास्तव में हालत यह है कि यह केवल बढ़िया शब्द ही हैं । लोगों में वैसे भूखमरी, गरीबी जनसंख्या, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और पक्षपात बढ़ा है । स्थिति यह है कि आज सर्वत्र निराशा का वातावरण देश भर में फैला हुआ है । यह खेद की बात है कि शासक दल के नकली साम्यवादी, समाजवादी समाज का नारा तो लगाते हैं, परन्तु उन्हें इसके अर्थ बिल्कुल मालूम नहीं हैं । ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार केन्द्रीकृत आयोजना तथा राष्ट्रीयकरण के लिए कटिबद्ध है । मेरे विचार में अन्य देश इस पथ को छोड़ रहे हैं । यहां तक कि साम्यवादी देश भी इससे विरक्त हो रहे हैं । वह भी इस मामले में अब काफी संशोधन कर रहे हैं । श्री खुश्चेव जैसे लोग भी कहते हैं कि अव्यवहारिक साम्यवादी आर्थिक योजनाओं को छोड़ देना चाहिये ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair.]

कृषि के मामले में हमेशा ऊपर से हस्तक्षेप होता रहा है । उत्पादक के लिये कोई प्रेरणा नहीं मिलती रही । खाद मंत्रालय का काम ठीक ढंग से नहीं चलता रहा । आज भी दो जून रोटी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही । सिद्धांतों को भी ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा । सहकारी खेती इत्यादि से उत्पादन बढ़ने के स्थान पर कम हुआ है । इससे किसानों में काफी क्रांति भी फैली है । मेरा यह आग्रह है कि सरकार को समझना चाहिए कि बिना प्रोत्साहन दिये उत्पादन नहीं बढ़ेगा । कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना होगा । खेद की बात है कि हमारी सरकार बिल्कुल इसकी विपरीत दिशा में जा रही है । संविधान का सत्रहवां संशोधन इस दिशा में एक और एक बहुत बड़ा धक्का होगा । इससे सारा प्रोत्साहन वैसे ही समाप्त हो जायेगा ।

मैं समाजवादी आयोजन के विरूद्ध नहीं हूं परन्तु मेरा कहना यह है कि रूसी ढंग के आयोजन के स्थान पर सम्मति से किया गया आयोजन होना चाहिए । लोगों के मूलभूत अधिकारों को हड़प नहीं किया जाना चाहिए । एक बात तो हमारी सरकार को स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि वर्तमान ढंग के आयोजन से लोकतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना असम्भव है । मैं तो इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पक्षपात तथा चोरबाजारी को समाप्त करने के प्रयत्न किये जाने चाहियें । यदि ऐसा न हुआ तो समस्त उच्च आदर्श मिट्टी में मिल जायेंगे । इसी बात को २६ जनवरी को हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा था ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री बदरूद्दुजा (मर्शिदाबाद) : मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि श्री नेहरू अरोग्य हो गये । ईश्वर उन्हें लम्बी उमर दे । उनका देश के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में विशेष स्थान है । मुझे इस बात का खेद है कि उपराष्ट्रपति के अभिभाषण में उन भीषण कठिनाईयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया जिनसे कि हाल ही दंगो में मुसलमानों को कलकत्ते में दो चार होना पड़ा । इससे भारत में अल्प संख्यकों के मित्र भी हिल उठे । मुझे इस बात का खद है कि पूर्वी बंगाल की बातें तो बढ़ा चढ़ा कर की गयी, परन्तु पश्चिमी बंगाल के मुसलमानों की यातनाओं को बहुत ही कम करके दिखाया गया है एक दो साम्यवादी नेताओं ने जरूर उन्हें व्यक्त करने का साहस किया है । सदन में बहुत कम लोगों ने इस ओर ध्यान दिया है । यहां तक कि कुछ अखबार भी इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं । हमारे गृह-कार्य मंत्री जी ने अपना ध्यान पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं पर ही केन्द्रित रखा है और जो दु:ख पश्चिमी बगाल के मुसलमानों ने उठाये हैं उसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों पर भारी अत्याचार किये गये हैं । उन्हें कम करके नहीं दिखाया जा सकता परन्तु आप इस बात की भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल के दंगो में मुसलमानों को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है । और उन दंगो को पश्चिमी बंगाल के कुछ एक अखबारों ने उकसाया है । मेरे हृदय में गृह-कार्य मंत्री के लिए बहुत आदर है । पश्चिमी बंगाल में दंगों को दबाने का श्रेय उन्हीं को है । राज्य के अधिकारियो ने तो कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया । पुलिस ने दंगा करने वालों का साथ दिया । और इन्हीं लोगों ने मुसलमानों के घरो में आग लगाई और कईयों को मार गिराया । भारतीय साम्यवादी दल तथा उसके नेताओं के अतिरिक्त सभी दल तथा वर्ग कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल के अन्य भागों में होने वाली घटनाओं को तमाशा समझ कर चुपचाप देखते रहे । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने इन दंगों में बहुत काम किया, उनकी मैं सराहना करता हूं ।

मैं धर्मनिर्पेक्षता में विश्वास करता हूं किन्तु प्रजातंत्र के ऊपरी दिखावे में विश्वास नहीं करता । हम कांग्रेस में विद्यमान सभी प्रगतिशील वर्गों के सहयोग, सहायता तथा सहानुभति के साथ भारत की उन्नति के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ।

मझे अपनी मातृभमि संसार की सब वस्तुओ से अधिक प्रिय है । इसके सामने मेरे लिए संसार के सारे एश्वर्य तुच्छ हैं । मुसलमान समझते हैं कि भारत उनकी मातृभूमि है और उन्हें चाहे कितनी भी यातनायें सहनी पड़ें वे अपनी मातृभूमि छोड़कर नहीं जायेंगे । दोनों देशों की सरकारों का कर्तव्य है कि वह अल्पसंख्यको की रक्षा करें, क्योंकि दोनों ही देशों में, सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में, अल्प संख्यक सुरक्षित नहीं हैं । उनके प्राण दांव पर लगे हुए हैं ।

दंगे के दिनों में जिस भारतीय जनता ने मुसलमानों के प्राणों की रक्षा की और जिन्होंने उन्हें पेट भर भोजन दिया है, मैं उनको हार्दिक धन्यबाद देता हूं । केन्द्र सरकार ने दंगों को दबाने में बहुत सराहनीय कार्य किया है जिसके लिये वह बधाई की पात्र है ।

श्री नि० रं० घोष (जलापाईगड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है कि भारत विरोधी तत्वों ने जो भारत में पाकिस्तान के लिये कार्य कर रहे हैं, यह प्रचार किया है कि कलकत्ता में हुए दंगों में एक भी मुसलमान जीवित नहीं बचा है । कलकत्ता में हुई घटनाओ की तुलना पूर्वी पाकिस्तान में हुए साम्प्रदायिक दंगो से की गई है । ऐसा विश्व के सामने पाकिस्तान में अल्प संख्यको के साथ किये गये अमानवीय अत्याचारों पर पर्दा डालने के लिए किया गया है ।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हुआ है वह वर्णनीय नहीं है। वहां पर गांव के गांव जला कर राख कर दिये गये। बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं को जीवित आग में भून दिया गया। कुछ कर्तव्यनिष्ठ समाचारपत्रों ने इन घटनाओं का वास्तविक चित्र संसार के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था किन्तु पाकिस्तान सरकार ने उनका मुंह बन्द कर दिया।

भारत और पाकिस्तान की नीति संबंधी रवैये में कितना अन्तर है यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि विभाजन के समय पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिन्दू थे किन्तु पाकिस्तान सरकार के अत्याचारों के परिणामस्वरूप यह संख्या इस समय थोड़ी ही रह गई हैं जब कि भारत में पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों के कारण यहां मुसलमानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। पाकिस्तान के शेष अल्पसंख्यक भी भारत आना चाहते हैं।

कलकत्ता में हुये दंगों के लिए पाकिस्तान के समर्थक उत्तरदायी है। इन लोगों ने वहां पर लोगों को दंगों के लिए भड़काया उनका उद्देश्य था कि कलकत्ता में दंगे करा कर पूर्व पाकिस्तान में हुये दगों के बारे में लोगों की धारणा बदली जाये तथा भारत में हुई घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर अन्य देशों के सामने प्रस्तुत किया जाये।

यह कहना गलत है कि कलकत्ते में हिन्दुओं ने दंगों की पहल की। वास्तव में सर्वप्रथम मुसलमानों ने ही वहां पर विद्यार्थियों पर आक्रमण किया। कई स्थानों पर हिन्दुओं पर आक्रमण किये गये और लूटमार की गई। इन दंगों में मुसलमानों की अपेक्षा अधिक हिन्दू मारे गये। यह लज्जा की बात है मुर्शिदाबाद में जहां के प्रतिनिधि उस समय यहां विद्यमान हैं—पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगाये गये और पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। फिर भी हमने इस बात को सहन किया।

दंगे आरम्भ होने से पहले पाकिस्तानी जासूस तथा कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति मैं नाम लेना नहीं चाहता हू—पाकिस्तान के उपउच्चायुक्त से मिले और बाद में उन्होंने विभिन्न स्थानों में जाकर मुसलमानों को भड़काने का कार्य आरम्भ कर दिया। पाकिस्तान के समर्थक मुस्लिम इलाकों में गये और उनमें साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित किया। वहां पर इन दंगों को करवाने की पूर्व योजना थी जो इस बात से सिद्ध हो जाती है कि दगे आरम्भ होने से कुछ दिन पूर्व बड़े मुसलमान व्यापारियों ने दंगे बीमा, करवा लिये थे। इन दंगों की सूचना पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिये कलकत्ता में फोटो लिए गये और टेप रिकार्ड द्वारा सब घटनाओं को रिकार्ड किया ताकि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यको के साथ अधिक अमानवीय अत्याचार किया जा सके। इन दगों की सूचनायें बढ़ा चढ़ा कर पाकिस्तान को भेजी गईं।

कलकत्ता में हुए दंगों को शीघ्र ही कड़ी कार्यवाही करके दबाया गया पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ भी अमानवीय व्यवहार अल्पसंख्यकों के साथ किया गया सरकार ने उन्हें कम करके बताया है। किन्तु हमारी पाकिस्तान को सतुष्ट करने वाली नीति से कोई लाभ नहीं हुआ है।

पाकिस्तान से हजारों की संख्या में मुसलमान अवैध रूप से भारतीय क्षत्र में घुस आये और उनके रिश्तेदार उन्हें यहां पर आश्रय दे रहे हैं। इतनी संख्या में पाकिस्तानियों का भारत में आना भारत के लिए खतरे से खाली नहीं है। सरकार को इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिए दृढ़ कदम उठान चाहिएं। ये सारे मामले सरकार को विश्व के राष्ट्रों के सामने स्पष्ट रूप में रखने चाहिएं।

अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को बता दिया जाना चाहिए कि हमारा संविधान देश-द्रोहियों और विश्वासघाती लोगों की रक्षा नहीं करता। इस प्रकार की कार्यवाही करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में शुद्धि

CORRECTION TO STATEMEN TBY MINISTER

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं आज गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में एक साधारण शुद्धि करने की अनुमति चाहता हूं । हजरबल चोरी कांड में गिरफ्तार किये गये तीन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं : अब्दुल रहीम बांदी, अब्दुल रशीद और गुलाम मुहम्मद भट्ट । 'गुलाम मुहम्मद भट्ट' का नाम गलती से बताया गया है । यह 'कादिर बट्ट' होना चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : आपने गिरफ्तार तो इस व्यक्ति को किया और नाम दूसरे का बता दिया ?

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, १८ फरवरी, १९६४/२९ माघ, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday February 18, 1964 Magha 29, 1885 (Saka)

GMGIPND—LS III—2202(ai) LS—14- 5-64—600.